घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 215- शनिवार 06- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सूरत आज स्वच्छता का रोल मॉडल ही नहीं बल्कि ऊर्जावान शहर भी है : पीएम मोदी

सूरत,05 जून 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सूरत स्वच्छता का रोल मॉडल ही नहीं बल्कि ऊर्जावान शहर भी है। उन्होंने कहा कि कभी प्लेग जैसी गंभीर महामारी से प्रभावित रहा सूरत आज देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल होकर पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है। उन्होंने कहा कि सूरत केवल एक शहर नहीं अपितु एक ऊर्जावान और जनशक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सूरत के इंडोर स्टेडियम में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत स्थानीय अंदाज में 'केम छो बधा,आपडू सूरत मजामा ने?' कहकर की,जिससे उपस्थित जनसमूह में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने गुजरात और सूरत की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोगों ने भाजपा की सेवा और विकास की राजनीति को लगातार समर्थन दिया है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में मिले प्रचंड जनादेश को उन्होंने जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत केवल राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि विकास और जनसेवा के मिशन को आगे बढ़ाने की नई जिम्मेदारी भी है। उन्होंने 'विकसित गुजरात, विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। स्थानीय निकाय चुनावों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अभूतपूर्व विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और किसी भी राजनीतिक दल को इतने लंबे समय तक लगातार जनसेवा का अवसर मिलना दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई दशकों से गुजरात की जनता भाजपा को निरंतर आशीर्वाद दे रही है और समय के साथ यह विश्वास और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सूरत में एक लाख से अधिक लोगों ने पांच दिनों तक चलाए गए विशेष अभियान में भाग लेकर शहर से कचरा एकत्र किया। उन्होंने इसे अपने लिए सबसे बड़ा उपहार बताते हुए सूरतवासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनभागीदारी से ही पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि भारत आज 'प्रकृति के साथ प्रगति' के मंत्र को अपनाकर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को पहचानते हुए गुजरात ने वर्षों पहले ही दूरदर्शी कदम उठाए थे। इस सदी की शुरुआत में राज्य में जलवायु परिवर्तन के लिए अलग विभाग की स्थापना की गई थी, जो देश में अपनी तरह की पहली पहल थी। उन्होंने पाटन जिले के चारणका में देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का उल्लेख करते हुए कहा कि गुजरात ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि आज भारत हरित ऊर्जा और टिकाऊ विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर है और भारत भी हरित विकास को केंद्र में रखकर नई विकास रणनीति पर कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री ने सूरत में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं शहर और राज्य के विकास को नई गति प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों को विश्वास है कि देश सुरक्षित हाथों में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती को विकास के अवसर में बदलने का कार्य किया है और उनके नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण तथा विकास के बीच संतुलन स्थापित करते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

संक्षिप्त समाचार

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अगले वायु सेना उप प्रमुख
एक जुलाई को संभालेंगे पद

नई दिल्ली,05 जून 2026। केंद्र सरकार ने फाइटर पायलट एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को फिर से वायु सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। जाने-माने टेस्ट पायलट एक जुलाई को अपना नया पद संभालकर वायु सेना में सबसे अहम लीडरशिप पदों में से एक की जिम्मेदारी लेंगे। उनकी नियुक्ति ऐसे अहम समय पर हुई है, जब भारतीय वायु सेना अपने आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने पहली बार 15 मई, 2023 को एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर उप वायु सेना प्रमुख का पदभार संभाला था। एयर मार्शल एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होने के साथ-साथ एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट भी हैं। उन्हें मिग-21, मिग-29 और मिराज-2000 जैसे विभिन्न प्रकार के विमानों को उड़ाने का अनुभव भी है। पिछले 23 सालों से आशुतोष दीक्षित वायुसेना का हिस्सा रहे हैं। अपने अब तक के कार्यकाल में दीक्षित ने 20 से अधिक प्रकार के विमानों पर 3300 घंटे की उड़ान भरी है। उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर और रक्षक में भाग लिया है। उन्होंने भविष्य की प्रौद्योगिकियों को अपनाने से संबंधित कई परियोजनाओं का नेतृत्व किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि भारतीय वायु सेना 'आत्मनिर्भरता' पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए आधुनिकीकरण हासिल करे। उप वायु सेना प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान एलसीए मार्क-1ए, मार्क-2 और एएमसीए सहित कई स्वदेशी विमान परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

डेटा सेंटर कंपनी एयरट्रंक ने भारत में तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की

नई दिल्ली,05 जून 2026। ऑस्ट्रेलिया की हाइपरस्केल डेटा सेंटर कंपनी एयरट्रंक ने भारत में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को एयरट्रंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा करते हुए कहा कि भारत की डिजिटल अवसंरचना यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। एयरट्रंक ने भारत में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश तथा 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना घोषणा की है। यह देश के डिजिटल अवसंरचना क्षेत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस निवेश से क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। साथ ही इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा मिलेगा और नवाचार आधारित विकास को गति मिलेगी।

दिल्ली हाईकोर्ट से 'कॉकरोच जनता पार्टी' को राहत...
प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली,05 जून 2026। दिल्ली होईकोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं को उठाया गया था हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में राहत देने से मना कर दिया, जिससे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के आयोजन पर फिलहाल रोक नहीं लग सकी। याचिका में यह दलील दी गई थी कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो सकती है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि, कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता को नहीं माना और इस संबंध में कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। इस फैसले से कॉकरोच जनता पार्टी को अपने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है।

कर्नाटक में डी.के. शिवकुमार को झटका
विभाग बंटवारे से नाराज रामलिंगा रेड्डी ने छोड़ा मंत्री पद,बोले-पार्टी में बना रहूंगा...

बेंगलुरू,05 जून 2026। कर्नाटक सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्री रामलिंगा रेड्डी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। जल संसाधन (वाटर रिसोर्सेज) विभाग मिलने से असंतुष्ट रेड्डी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका इस्तीफा केवल मंत्री पद से है, कांग्रेस पार्टी से नहीं। इस्तीफे के बाद रामलिंगा रेड्डी ने कहा, 'मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम नहीं कर सकता, इसलिए मंत्री पद छोड़ रहा हूं।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह विधायक बने रहेंगे और कांग्रेस पार्टी से उनका नाता कायम रहेगा। रेड्डी ने कहा कि वह पिछले 53 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी किसी से मंत्री पद की मांग नहीं की। उन्होंने याद दिलाया कि वे पूर्व मुख्यमंत्री एम. वीरप्पा मोइली और एस.एम. कृष्णा की सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं और पार्टी ने हमेशा उन पर भरोसा जताते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार रात अपने 13 मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन किया था। इस दौरान रामलिंगा रेड्डी को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक रेड्डी बेंगलुरू विकास विभाग मिलने की उम्मीद कर रहे थे और इसी विभाग पर उनका दावा था। जानकारी के अनुसार, विभागों के आवंटन को लेकर गुरुवार को हुई बैठक के दौरान रेड्डी ने अपनी नाराजगी जाहिर की और बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को वर्ष 2023 में किए गए उस कथित वादे की भी याद दिलाई, जिसमें भविष्य में कैबिनेट फेरबदल होने पर उन्हें बेंगलुरू विकास विभाग सौंपने की बात कही गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठ बार विधायक रह चुके रामलिंगा रेड्डी ने बेंगलुरू विकास विभाग के अलावा कोई अन्य मंत्रालय स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद उन्हें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सौंपा गया। वहीं, कर्नाटक सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में गिने जाने वाले बेंगलुरू विकास विभाग की जिम्मेदारी कृष्णा बायरे गौडा को दी गई है।

असम मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार,12 विधायकों को ने ली मंत्री पद की शपथ

गुवाहाटी,05 जून 2026। लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए असम मंत्रिमंडल का शुक्रवार को विस्तार किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व वाली सरकार में 12 एनडीए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस विस्तार के साथ 19 सदस्यीय प्रस्तावित मंत्रिमंडल में अब तक 17 पदों को भर दिया गया है। नवनियुक्त मंत्रियों में 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हैं, जबकि एक विधायक सहयोगी दल असम गण परिषद (अगप) से हैं। ज्योति-बिष्णु अंतरराष्ट्रीय कला मंदिर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले मंत्रियों में डॉ. रणोज पेगू, अश्विनी राय सरकार, विश्वजीत दैमारी, पीयूष हजारिका,अशोक सिंघल,कृष्णेंदु पाल, नीलिमा देवी,जयंत मल्ल बरुवा,कौशिक राय, बिमल बोरा,सुशांत बरगोहाईं और केशव महंत शामिल हैं। इनमें केशव महंत एकमात्र अगप विधायक हैं,जबकि शेष सभी भाजपा से संबंधित हैं। उल्लेखनीय है कि शपथ लेने वाले मंत्रियों में चार को पहली बार मंत्रिमंडल में स्थान मिला है।

वहीं, सहयोगी दल असम गण परिषद से अब मंत्रिमंडल में दो प्रतिनिधि अतुल बोरा और केशव महंत शामिल हैं। इसी प्रकार, एनडीए के एक अन्य सहयोगी दल बीपीएफ का प्रतिनिधित्व चरण बोरो कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने पटना उच्च न्यायालय की 48 वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ...

पटना,05 जून 2026। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। बिहार लोकभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने औपचारिक रूप से मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल लिया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री राम कृपाल यादव, न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी तथा विभिन्न क्षेत्रों की अनेक गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहीं। शपथ ग्रहण के बाद उपस्थित लोगों ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू के सेवानिवृत्त होने के बाद यह महत्वपूर्ण दायित्व संभाला है। न्यायमूर्ति साहू चार जून 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके बाद न्यायमूर्ति राय ने पांच जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वह पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय का जन्म 12 जुलाई 1964 को सिक्किम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गंगटोक स्थित ताशी नामग्याल अकादमी (तत्कालीन नामगचेन स्कूल) में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा के क्रम में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से वर्ष 1989 में एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1990 में वह दिल्ली बार एसोसिएशन में नामांकित हुईं और दिल्ली उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। इसी दौरान उन्होंने सिक्किम न्यायिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और न्यायिक सेवा में प्रवेश किया। उन्होंने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सहित न्यायपालिका के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए लंबा अनुभव अर्जित किया। न्यायिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर उन्हें 15 अप्रैल 2015 को सिक्किम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह सिक्किम उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश भी रहीं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की और न्यायिक प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाई।

तमिलनाडु में भाजपा छोड़ते ही अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाई...अगला चुनाव लड़ने का ऐलान

कहा...मतभेद थे,आलाकमान ने चुनाव तक रुकने को कहा था...

चेन्नई,05 जून 2026। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शुक्रवार को नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज में अन्नामलाई ने कहा कि आज हम एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु में 2031 में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मेरे लिए यह तय करना बहुत मुश्किल था कि मैं बीजेपी का सदस्य रहूं या तमिल लोगों से जुड़ा रहूं। मैंने 4 दिसंबर 2025 को पार्टी को बताया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। पार्टी ने मुझसे कहा कि पहले चुनाव हो जाने दें, फिर जाएं। अन्नामलाई ने 2 जून को भाजपा से इस्तीफा दिया था। लेटर शुक्रवार को सामने आया। उन्होंने इस्तीफे की वजह बताते हुए लिखा कि पिछले 18 महीनों से आलाकमान के साथ उनके मतभेद चल रहे हैं। अब उनके विचार एक जैसे नहीं रहे। अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। नौकरी छोड़कर 2020 में भाजपा से जुड़े। पार्टी ने पहले उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष बनाया। अन्नामलाई के रहते हुए बीजेपी ने 2021 और 2026 विधानसभा चुनाव लड़ा। दोनों ही चुनावों में भाजपा का वोट शेयर 2% से ज्यादा नहीं बढ़ सका। पीएम मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरित होकर मैं 6 साल पहले भाजपा में शामिल हुआ था। मेरा मकसद तमिलनाडु में बदलाव लाना और राज्य में राजनीति के तौर-तरीकों को बेहतर बनाना था। मैं बीजेपी नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझ जैसे युवा और अनुभवहीन व्यक्ति पर भरोसा करके बड़ी जिम्मेदारियां और नेतृत्व के पद सौंपे। राज्य की जनता कई दशकों से चली आ रही आम राजनीतिक चर्चाओं से ऊब चुकी थी और बदलाव चाहती थी। पिछले दशक में कई बार बदलाव की लहरें उठीं, लेकिन वे टिक नहीं पाईं। पिछले 18 महीनों में टॉप लीडरशिप के साथ कुछ मतभेद रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति को आगे बढ़ाने के तरीके को लेकर उनके और पार्टी नेतृत्व के विचार अब मेल नहीं खाते।

मणिपुर में 47 करोड़ की चार लाख याबा गोलियां बरामद,एक गिरफ्तार

इम्फाल,05 जून 2026। मणिपुर के जिरीबाम जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए एक बड़े संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों ने लगभग 47 करोड़ मूल्य की चार लाख याबा गोलियां बरामद की हैं। इस मामले में बिहार निवासी एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, विशेष खुफिया सूचना के आधार पर गुरुवार दोपहर जिरीबाम जिले के लेंगांगपोकपी क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में असम राइफल्स,मणिपुर पुलिस,केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा इंडिया रिजर्व बटालियन के जवान शामिल थे। संयुक्त दल ने एक टाटा मालवाहक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। जांच के दौरान वाहन में छिपाकर रखी गई चार लाख याबा गोलियां बरामद की गईं।

राज्यसभा चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खरगे ने नामांकन दाखिल किया

नई दिल्ली,05 जून 2026। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। राज्यसभा चुनाव 18 जून को होना है। नामांकन दाखिल करने के दौरान केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार,पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया,रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद सहित अनेक प्रमुख नेता उपस्थित थे। शुक्रवार को बेंगलुरु स्थित विधान सौधा में एआईसीसी अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष औपचारिक रूप से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उनकी उम्मीदवारी को पार्टी के सभी विधायकों और नेताओं का एकजुट समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। सभी विधायक और पार्टी के नेताओं ने मुझे उम्मीदवार के रूप में चुना है। मैं उनके विश्वास और समर्थन के लिए उनका आभारी हूं। खरगे ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत को लेकर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया।

मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा...
आदिवासी गांव पर हमले में तीन की मौत

नई दिल्ली,05 जून 2026। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में शुक्रवार को एक बार फिर हिंसा की घटना सामने आई। अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने एक आदिवासी बहुल गांव पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई। हमले के दौरान कई मकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस के अनुसार, हथियारबंद लोगों के एक समूह ने लोइबोल खुल्लेन गांव पर अचानक हमला कर दिया। हमले के जवाब में वहां मौजूद दूसरे सशस्त्र समूह ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों पक्षों के बीच करीब आधे घंटे तक चली फायरिंग में तीन ग्रामीणों की जान चली गई। मृतकों की पहचान लेतखोंगाम हाओकिप, उनकी पत्नी टिनमैरी हाओकिप और जांगमिनलाल हाओकिप के रूप में हुई है। गोलीबारी के दौरान ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर आसपास के जंगलों की ओर भाग गए।

बीएसएफ त्रिपुरा से बंगाल व बिहार तक,सीमा पर हर चुनौती का कर रही है सामना : अमित शाह

त्रिपुरा,05 जून 2026। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को त्रिपुरा के लंकामुड़ा स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की लंकामुड़ा सीमा चौकी (बीओपी) का निरीक्षण किया और सीमा प्रहरियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने अगरतला में पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमें देश को स्मगलिंग,मानव तस्करी,देश के युवाओं को नशे से सुरक्षित करना होगा। नारकोटिक्स हो, मानव तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग या ड्रोन की चुनौती, बीएसएफ त्रिपुरा से बंगाल और बिहार तक, सीमा पर हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर रही इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा, केन्द्रीय गृह सचिव, सीमा प्रबंधन और महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सामाजिक समरसता,अखंडता और आत्मसम्मान के प्रति समर्पित गुरुजी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भले ही नई पीढ़ी को गुरुजी के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनके विचार आज भी राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि पौरोपण को केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि जन-आंदोलन और जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा।

C M Y K

संपादकीय

संसाधनों के संयमित उपयोग का समय

सुबह अखबार हाथ में आते ही देश-दुनिया की बड़ी खबरों के बीच नजर अक्सर महंगाई पर टिक जाती है।'रसोई गैस का संकट', 'सब्जियों के बढ़ते दाम या'कमजोर होता रुपया'-ये सिर्फ सुर्खियां नहीं,बल्कि मध्यमवर्गीय परिवारों के बजट,बच्चों की फीस और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी रोजमर्रा की चिंताएं हैं। बदलते मौसम की मार सभी वर्गों की मुश्किलें अलग से बढ़ा रही है। देखा जाए तो ये दोनों चिंताओं की कड़ी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी है। हमें समझना होगा कि पर्यावरण का सीधा संबंध हमारी रसोई,बिजली के बिल,मोटरसाइकिल की टंकी और खेतों की मिट्टी से है।

हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, जैविक खेती को अपनाने और ईंधन की खपत घटाने,अनावश्यक विदेशी यात्राओं और सोने की खरीद से बचने और यथासंभव 'वर्क फ्राम होम' अपनाने की अपील की। उन्होंने इस दशक को 'संकटों का दशक' बताते हुए कहा कि कोविड-19, युद्ध और ऊर्जा संकट जैसी वैश्विक चुनौतियां विकास और गरीबी उन्मूलन की उपलब्धियों पर असर डाल रही हैं। इस वैश्विक परिदृश्य को वित्तीय मामलों के जानकार राबर्ट कियोसाकी की गंभीर चेतावनियों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। उनका तर्क है कि सभ्यताओं का पतन किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि आंतरिक महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता और संसाधनों के दुरुपयोग से होता है। प्रधानमंत्री की अपील के संदर्भ की ही बात करें तो आज भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल और 50 प्रतिशत प्राकृतिक गैस आयात करता है।

होर्मुज जलमार्ग में गतिरोध के चलते उपजे भू-राजनीतिक संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें सौ डालर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं,जिससे देश का आयात बिल तेजी से बढ़ा है। इसी बीच डालर मजबूत होने से रुपया गिरकर लगभग 95 रुपये प्रति डालर के रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंच गया,जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब और देश की आर्थिक संप्रभुता पर पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में हमारे देश की कृषि नीति इस संकट से निपटने का मजबूत माध्यम बन सकती है। भारत अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक यूरिया का लगभग 70 प्रतिशत विदेशों से आयात करता है। यूरिया निर्माण में प्राकृतिक गैस के उपयोग के कारण वैश्विक गैस संकट सरकारी उर्वरक सब्सिडी बजट को कई गुना बढ़ा देता है।

ऐसे में हमें जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती की ओर तेजी से बढ़ना होगा। गाय के गोबर और गोमूत्र आधारित जैव-इनपुट्स, कंपोस्टिंग और बायोगैस स्लरी के विकेंद्रीकृत उपयोग से रासायनिक यूरिया पर निर्भरता काफी घटाई जा सकती है। यह केवल मिट्टी की सेहत सुधारने का पारंपरिक उपाय नहीं,बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार बचाने वाला एक क्रांतिकारी 'कृषि-संयम' है, जो देश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाता है।

भारत ने अतीत में भी बड़े संकटों का सामना सामूहिक त्याग से किया है। जैसे 1962 के युद्ध में माताओं का स्वर्ण दान और 1965 के अन्न संकट में लाल बहादुर शास्त्री की अपील पर पूरे देश द्वारा सप्ताह में एक दिन का उपवास। आज का संकट उतना कठिन नहीं है। वर्तमान प्रधानमंत्री का ऊर्जा संरक्षण और मितव्ययिता का आह्वान हमारे पूर्वजों के त्याग की तुलना में सरल और व्यावहारिक है। हमें बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में थोड़ा अनुशासन और संयम लाना है।

संयमित जीवन हमारी सांस्कृतिक चेतना का मूल है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी के पास हर मनुष्य की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं,लेकिन किसी एक के लालच को शांत करने के लिए नहीं। यही भाव आज भारत के 'लाइफ मिशन का आधार है। इसी संदर्भ में कबीर की सीख भी उतनी ही प्रासंगिक है कि 'साईं इतना दीजिए,जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूखा ना रहूं,साधु न भूखा जाय॥' तात्पर्य यही है कि आवश्यकता और लालच का अंतर समझने पर मितव्ययिता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक कर्तव्य एक 'राष्ट्रीय संयम यज्ञ' बन जाती है।

एक आम नागरिक के रूप में हम इस संयम यज्ञ में छोटी-छोटी लेकिन प्रभावी आदतों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके लिए बड़े आर्थिक त्याग की आवश्यकता नहीं है,बल्कि दैनिक जीवन में अनुशासन और जागरूकता अपनाने की जरूरत है। हमें ऊर्जा और जल संरक्षण को अपनी आदत बनाना चाहिए। एलईडी बल्ब और ऊर्जा-दक्ष उपकरणों का उपयोग को बढ़ावा दें। कमरे से निकलते ही लाइट और पंखे तुरंत बंद करें। पानी का विवेकपूर्ण उपयोग भी उतना ही आवश्यक है। साझा सवारी,साइकिल और पैदल चलने को प्राथमिकता देना भी आवश्यक है।

हमने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन विकसित राष्ट्र का वास्तविक अर्थ केवल जीडीपी में बढ़ोतरी या बड़ी औद्योगिक इमारतों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। सच्चा विकास वही है, जहां ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ हो और संसाधनों का वितरण न्यायसंगत हो। यदि हम अपनी उपभोगवादी जीवनशैली में बदलाव नहीं लाते हैं,तो वैश्विक बाजार के झटके हमारे सपनों को बाधित करते रहेंगे। काउंसिल आन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर-सीईईडब्ल्यू के अनुसार यदि भारत अभी से संसाधन-कुशल मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो वर्ष 2047 तक यह हरित अर्थव्यवस्था देश में 1.1 ट्रिलियन डालर (लगभग 97.7 लाख करोड़) का नया बाजार मूल्य सृजित कर सकती है, जिससे लगभग 4.8 करोड़ नए रोजगार के अवसर तैयार हो सकते हैं।

मितव्ययिता और ऊर्जा-संयम कोई नकारात्मक विचार नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण के वे संक्रमणकालीन अनुशासन हैं जो हमें दीर्घकालिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हैं। हम यह साझा संकल्प लें कि हम अपने घरों में संयम और जैविक खेती की नई चेतना का संचार करेंगे । आज हमारे द्वारा सहेजा गया पानी का प्रत्येक कतरा, बचाई गई बिजली की प्रत्येक इकाई और रासायनिक खाद के स्थान पर उपयोग किया गया प्राकृतिक इनपुट हमारे भविष्य की सुरक्षा का बीज बनेगा। यही छोटे-छोटे प्रयास विकसित राष्ट्र के विराट लक्ष्य की पूर्ति का माध्यम बनेंगे।

तृणमूल कांग्रेस में टूट और ममता की बढ़ती चिन्ताएं

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी),जिसने पिछले डे दशक से बंगाल की राजनीति पर लगभग एकाधिकार स्थापित कर रखा था,आज आंतरिक असंतोष,नेतृत्व संबंधी प्रश्नों और जनविश्वास के संकट से जूझती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर असंतुष्ट नेताओं और विधायकों की गतिविधियों ने यह संकेत दिया है कि संगठनात्मक एकता में दरारें उभर रही हैं। यह स्थिति केवल किसी एक राजनीतिक दल का संकट नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में राजनीतिक मूल्यों,जनभावनाओं और नेतृत्व की भूमिका पर पुनर्विचार का अवसर भी है। राजनीति में इतिहास बार-बार यह प्रमाणित करता रहा है कि जब भी सत्ता के साथ अहंकार जुड़ता है, जनता अंततः उसका उत्तर देती है। लोकतंत्र में जनता ही अंतिम निर्णायक होती है। चाहे वह इंदिरा गांधी का आपातकाल हो,पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन या दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अंत या फिर उत्तर प्रदेश एवं बिहार की अनेक राजनीतिक घटनाएँ-हर जगह जनता ने यह संदेश दिया है कि सत्ता जनता की सेवा के लिए है,शासन के अहंकार के लिए नहीं।

ममता बनर्जी को कभी संघर्षशील, जुझारू और जननेता के रूप में देखा जाता था। उन्होंने वामपंथी शासन के लंबे दौर को समाप्त कर बंगाल में परिवर्तन का नया अध्याय लिखा। किंतु समय के साथ उनकी राजनीति पर अहंकारवाद, व्यक्तिवाद और तुष्टिकरण के आरोप बढ़ते गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के भीतर निर्णय प्रक्रिया का अत्यधिक केंद्रीकरण और कुछ व्यक्तियों का बे ता प्रभाव अनेक वरिष्ठ नेताओं को असहज करता रहा है। यही कारण है कि समय-समय पर असंतोष के स्वर उभरते रहे हैं। राजनीतिक टिप्पणीकारों द्वारा प्रकाशित विश्लेषणों में भी यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि किसी दल में संगठन से अधिक व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाए,तो वहां असंतोष स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। हाल के घटनाक्रमों ने इस आशंका को और बल दिया है। जिस प्रकार पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता और विधायक नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि समस्या केवल व्यक्तियों की नहीं,बल्कि संगठनात्मक संस्कृति की भी है।

भारतीय राजनीति में हाल के वर्षों में आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। वर्ष 2013 से लेकर 2024 तक दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले केजरीवाल को जनता ने ईमानदार,पारदर्शी और वैकल्पिक राजनीति के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। लेकिन समय के साथ सत्ता का केंद्रीकरण,विरोधियों के प्रति असहिष्णुता,राजनीतिक अहंकार और स्वयं को अजेय मान लेने की प्रवृत्ति उनके नेतृत्व पर हावी होती दिखाई दी। जनता ने देखा कि जो दल कभी राजनीतिक शुचिता और नैतिकता की बात करता था, वह भी सत्ता के उसी मोह और व्यक्ति केंद्रित राजनीति का शिकार होता जा रहा है,जिसके विरुद्ध उसने संघर्ष प्रारम्भ किया था।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

परिणामस्वरूप दिल्ली की राजनीति में उसका प्रभाव कमजोर हुआ और जनता ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि लोकतंत्र में कोई भी नेता अथवा दल जनता से बड़ा नहीं होता। यह घटना इस सत्य को पुनः स्थापित करती है कि जनता लंबे समय तक अहंकार, अतिशयोक्ति और आत्म मुग्धता को स्वीकार नहीं करती।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के समक्ष खे ी चुनौतियों को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जब किसी दल का नेतृत्व स्वयं को संगठन और जनता से ऊपर मानने लगता है,तब असंतोष जन्म लेता है, कार्यकर्ता दूर होने लगते हैं और अंततः राजनीतिक आधार कमजोर पे ने लगता है। इतिहास बताता है कि लोकतंत्र में विनम्रता,संवाद,जनभावनाओं का सम्मान और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता ही स्थायी राजनीतिक सफलता की कुंजी हैं। किसी भी लोकतांत्रिक दल की शक्ति उसके विचार, संगठन और कार्यकर्ताओं में होती है, न कि केवल एक नेता में। जब दल विचारधारा की बजाय व्यक्तिपूजा पर आधारित होने लगते हैं, तब उनका संकट निश्चित हो जाता है। भारतीय राजनीति में अनेक उदाहरण हैं जहाँ परिवारवाद ने दलों की जे ों को कमजोर किया। महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पीछे भी नेतृत्व और उत्तराधिकार से जुड़े प्रश्न महत्वपूर्ण रहे। बंगाल में भी इसी प्रकार की चर्चाएँ समय-समय पर सामने आती रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के सामने दूसरा बड़ा संकट उसकी सार्वजनिक छवि का है। शिक्षक भर्ती, नगर निकायों तथा अन्य प्रशासनिक मामलों से जुड़े विवादों ने जनता के मन में अनेक प्रश्न खड़े किए हैं। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास होता है। यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही कम हो रही है, तो राजनीतिक नुकसान होना स्वाभाविक है।

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चल रही पहचान,नागरिकता, सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ से जुड़ी बहसों ने भी राजनीतिक वातावरण को प्रभावित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया। भाजपा का तर्क रहा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए और किसी भी प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति अंततः समाज को विभाजित करती है। यही कारण है कि बंगाल में भाजपा ने अपनी राजनीतिक रणनीति को राष्ट्रवाद,सांस्कृतिक पहचान और सुशासन के मुद्दों पर केंद्रित किया। भाजपा की बंगाल यात्रा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अध्ययन का विषय है। कभी केवल दो सीटों तक सीमित रहने वाली पार्टी आज राज्य की सत्ता शक्ति बन चुकी है। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे वर्षों का संगठनात्मक विस्तार,बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का निर्माण, राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता तथा स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श से जो ने की रणनीति रही है। भाजपा ने बंगाल में यह संदेश देने का प्रयास किया कि वह केवल एक राजनीतिक विकल्प नहीं,बल्कि वैचारिक विकल्प भी है। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि केवल राष्ट्रवाद या धार्मिक पहचान के आधार पर किसी दल की स्थायी सफलता सुनिश्चित नहीं होती। लोकतंत्र में जनता विकास, रोजगार,शिक्षा,स्वास्थ्य और सुरक्षा भी चाहती है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय भावना के साथ-साथ जनकल्याणकारी नीतियों को भी प्राथमिकता दे।

राष्ट्र और राजनीति का संबंध अत्यंत गहरा है। कोई भी राजनीतिक दल तभी दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकता है जब वह राष्ट्रहित,संविधान,लोकतांत्रिक मूल्यों और जनभावनाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहे। यदि कोई दल ऐसे तत्वों का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है जो राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध हों,तो जनता धीरे-धीरे उससे दूरी बनाने लगती है। भारत की लोकतांत्रिक चेतना इतनी परिपक्व हो चुकी है कि वह अंततः राष्ट्रहित और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करने वाले नेतृत्व को ही स्वीकार करती है। पश्चिम बंगाल का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य इसी सत्य की पुष्टि करता है। तृणमूल कांग्रेस के सामने चुनौती केवल बगावत या संगठनात्मक असंतोष नहीं है,बल्कि जनता के विश्वास को पुनः अर्जित करने की भी है। यदि पार्टी आत्ममंथन करती है,संगठन को लोकतांत्रिक बनाती है, पारदर्शिता बढ़ाती है और जनभावनाओं को समझने का प्रयास करती है, तो वह अपनी स्थिति को पुनः मजबूत कर सकती है। लेकिन यदि अहंकार, व्यक्तिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति जारी रहती है,तो संकट और गहरा सकता है। यही लोकतंत्र का शाश्वत सत्य है और यही पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीति का सबसे बड़ा सबक भी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सत्ता स्थायी नहीं होती, किंतु मूल्य स्थायी होते हैं। राजनीतिक दल आते-जाते रहते हैं, लेकिन जनता की अपेक्षाएँ और राष्ट्र की आवश्यकताएँ हमेशा बनी रहती हैं। जो दल इन अपेक्षाओं को समझते हैं,वे इतिहास बनाते हैं और जो इन्हें अनदेखा करते हैं,वे इतिहास बन जाते हैं। आज बंगाल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि तृणमूल कांग्रेस आत्मसुधार का मार्ग चुनती है या राजनीतिक पतन की ओर बढ़ती है।

शिक्षा के मंदिर में कोचिंग वॉर और दांव पर लगता मासूम छात्रों का भविष्य

अजय कुमार,
लखनऊ, उत्तरप्रदेश

बिहार के पटना का मुसल्लहपुर हाट इलाका देश भर में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की उम्मीदों का केंद्र माना जाता है। लेकिन हाल ही में इस इलाके से जो तस्वीरें और खबरें सामने आईं,उसने न केवल शिक्षा के इस मंदिर को शर्मसार किया है बल्कि बिहार की गौरवशाली ज्ञान परंपरा पर भी एक गहरा धब्बा लगा दिया है। जिन गलियों में सुबह से शाम तक किताबों के बंडल,पेन और कॉपियां दिखाई देती थीं,वहां अचानक पत्थरबाजी,लाठी-डंडे और हवाई फायरिंग की गूंज सुनाई देने लगी। यह विवाद महज दो कोचिंग संस्थानों की आपसी लड़ाई नहीं है,बल्कि यह शिक्षा के नाम पर चल रहे करोड़ों रुपये के उस बाजार का नग्न प्रदर्शन है,जहां छात्रों का भविष्य दांव पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ भीड़ और वर्चस्व की जंग लड़ी जा रही है। इस तथाकथित कोचिंग वॉर ने यह साबित कर दिया है कि जब शिक्षा व्यवसाय बन जाती है,तो नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का पतन किस कदर होता है।

इस पूरे बवाल की शुरुआत बेहद मामूली और बचकानी वजह से हुई,जिसे जानकर किसी भी सभ्य समाज का सिर घोर निराशा से झुक जाएगा। बताया जा रहा है कि एक कोचिंग संस्थान की ओर से बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में करीब 12 हजार छात्रों के सफल होने का दावा करते हुए बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। आरोप है कि यह पोस्टर प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के साइन बोर्ड के ऊपर या उसके बेहद करीब चिपका दिए गए। इसके बाद वर्चस्व की इस जंग में सीढ़ियां लगाकर बैनर फाड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। पोस्टर फाड़े जाने की इस छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते एक ऐसी आग का रूप ले लिया, जिसने पूरे इलाके के सुरक्षा तंत्र और कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दो पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए, लाठियां चलीं,ईंट-पत्थरों की बौछार हुई और देखते ही देखते वह परिसर कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो गया जहां हजारों छात्र अपने सुनहरे कल का सपना बुनने आते हैं।

घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया के महारथी और लाखों युवाओं के आदर्श बने शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर ने मीडिया के सामने आकर बेहद सनसनीखेज दावे किए। उन्होंने कैमरे के सामने पूरी गंभीरता से कहा कि उनके कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है और उन्होंने अपनी आंखों से एक-दो नहीं बल्कि आठ से दस राउंड फायरिंग होते हुए देखी है। एक शिक्षक के मुंह से इस तरह की बात सुनकर पूरे राज्य के अभिभावकों और छात्रों में दहशत फैल गई। लेकिन जब कानून के रक्षकों ने इस मामले की तहकीकात शुरू की और घटनास्थल के साथ-साथ आसपास की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, तो कहानी पूरी तरह पलट गई। पुलिस की शुरुआती जांच में दूर-दूर तक गोली चलने या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा फायरिंग करने का

कोई सबूत नहीं मिला। इसके उलट,सीसीटीवी में यह साफ दिखाई दिया कि खान सर के अपने ही सुरक्षा गार्ड हवा में हथियार लहराते और हमला करते नजर आ रहे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन दोनों गार्डों को हिरासत में ले लिया और खुद खान सर को भी देर रात लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा।

हैरानी की बात यह है कि जो शिक्षक रात में अपनी आंखों से गोलियां बरसने की गवाही दे रहे थे, सुबह होते-होते उनके सुर पूरी तरह बदल गए। वे अपने ही दावों से यू-टर्न लेते हुए यह कहने लगे कि अब पुलिस की जांच के बाद ही असलियत का पता चलेगा या फिर जब उनका घायल गार्ड ठीक होकर आएगा तब वह सच बताएगा। एक शिक्षक के बयानों में ऐसा विरोधाभास और तथ्यों को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही बेहद चिंताजनक है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कभी कहा था कि शिक्षक वह नहीं है जो केवल दिमाग में तथ्य ठूंसे, बल्कि वह है जो छात्र को सत्य की खोज के लिए तैयार करे। लेकिन आज के डिजिटल युग के इन तथाकथित गुरुओं के तथ्य और सत्य दोनों ही गंभीर संदेह के घेरे में आ गए हैं।

इस विवाद का दूसरा पहलू और भी भयावह है। फैजल खान की शिकायत पर पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को फौरन गिरफ्तार कर लिया। रौशन आनंद बिहार के एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद पटना की सड़कों पर एक नया ड्रामा शुरू हो गया। रौशन आनंद के समर्थन में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन करने लगे। छात्रों का आरोप है कि खान सर ने राजनीतिक और व्यावसायिक रंजिश के तहत उनके गुरु पर झूठे आरोप लगाए हैं। सोचिए,जिन नौजवानों को इस वक्त कमरों में बंद होकर परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, वे अपने-अपने पसंदीदा शिक्षकों के अंधविश्वास में सड़कों पर नारेबाज़ी कर रहे हैं और कानून को हाथ में लेने पर आमादा हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज के ये मशहूर यूट्यूब शिक्षक बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के बजाय अपने निजी स्वार्थ के लिए एक ट्रोल आर्मी और हिंसक भीड़ में तब्दील कर रहे हैं।

यह पहली बार नहीं है जब पटना की धरती पर कोचिंग संचालकों के कारण इस तरह का उपद्रव हुआ हो। इतिहास गवाह है कि साल 2019 में भी इसी मुसल्लहपुर इलाके में वर्चस्व को लेकर बमबाजी की घटना हुई थी। उस वक्त भी दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण इन दुकानदारों के हौसले बुलंद रहे। इस साल भी सरस्वती पूजा के मौके पर इसी तरह के हिंसक टकराव की खबरें आई थीं। अगर समय रहते पुलिस और प्रशासन ने इन व्यावसायिक संस्थानों पर नकेल कसी होती,तो आज यह नौबत नहीं आती। सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटरों में इसलिए मोटी फीस देकर भेजते हैं कि वे वहां से लहूलुहान होकर लौटें? अगर यह पत्थरबाजी दिन के वक्त होती, जब हजारों छात्र क्लास में मौजूद होते हैं, और किसी मासूम के सिर पर वह पत्थर लग जाता,तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या ये शिक्षक अपनी अकूत संपत्ति और टीआरपी के नशे में किसी बच्चे की जान की कीमत चुका पाते? इस पूरे खेल का सबसे कड़वा सच आर्थिक हितों का टकराव है। अक्सर यह प्रचारित किया जाता है कि कुछ शिक्षक बहुत कम पैसे में समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों संस्थानों के फीस स्ट्रक्चर की तुलना की जाती है,तो असलियत कुछ और ही निकलती है। जहां दो साल के ऑफलाइन कोर्स के लिए एक संस्थान किस्तों में दस हजार रुपये लेता है,वहीं दूसरा संस्थान एकमुश्त बीस हजार रुपये वसूलता है। ऑनलाइन कोर्सेस में भी फीस का अंतर जमीन-आसमान का है। जाहिर है, यह पूरी लड़ाई किसी शिक्षा सुधार या गरीब बच्चों के कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि यह अधिक से अधिक छात्रों को अपनी ओर खींचने और करोड़ों रुपये का टर्नओवर खड़ा करने की कॉरपोरेट जंग है।

अब इस मामले ने पूरी तरह से कानूनी मोड़ ले लिया है। पटना पुलिस ने कदमकुआं थाने में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भ्रामक जानकारी फैलाने की संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के बाद खान सर ने बड़ी ही चतुराई से बयान दिया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है और उनके गार्डों ने जो कुछ भी किया, वह आत्मरक्षा में किया था। वे कानून का सम्मान करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अतीत में उनका रिकॉर्ड कुछ और ही बयां करता है। चाहे वह रेलवे परीक्षा के दौरान छात्रों को उग्र आंदोलन के लिए भड़काना हो, बीपीएससी परीक्षा के समय अभद्र भाषा का प्रयोग करना हो या फिर हाल ही में नीट पेपर लीक मामले में एनकाउंटर जैसे उत्तेजक बयान देकर माहौल खराब करना हो, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है।

जब कोई मुख्यधारा का माध्यम इन कोचिंग संस्थानों की इस खतरनाक कार्यप्रणाली और उनके गिरते स्तर पर सवाल उठाता है, तो ये यूट्यूब शिक्षक अपने लाखों फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके डिजिटल लिंचिंग शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की एक फौज छोड़ दी जाती है,जो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर गाली-गलौज पर उतर आती है। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम जैसी विदेशी एनजीओ की रैंकिंग का हवाला देकर देश की पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जबकि वे खुद यह भूल जाते हैं कि वे शिक्षा के नाम पर कौन सा अनैतिक धंधा चला रहे हैं। लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। पटना की इस घटना ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के इन आधुनिक कुरुक्षेत्रों में अब ज्ञान की नहीं, बल्कि बंदूकों और पत्थरों की भाषा बोली जा रही है। सरकार और प्रशासन को अब बिना किसी दबाव के इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी, जो मिसाल बन सके, ताकि बिहार का कोई और होनहार छात्र इस गंदे व्यावसायिक खेल की बलि न चढ़े।

गरीब मरीज पूछ रहा है... क्या मेरा जीवन इतना सस्ता है?

प्रो. आरके जैन अरिजीत बड़वानी,मध्यप्रदेश

स्वास्थ्य व्यवस्था की असली परीक्षा अस्पतालों की इमारतों से नहीं, मरीज को समय पर मिलने वाले उपचार से होती है। दुर्भाग्य से, देश की चिकित्सा व्यवस्था के सर्वोच्च प्रतीकों में गिने जाने वाले एम्स भी अब लंबी प्रतीक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं। एम्स भोपाल में गैर-इमरजेंसी (रूटीन) केस में कई मरीजों को सीटी स्कैन या एमआरआई जैसी जरूरी जांच के लिए तीन-चार माह इंतजार करना पड़े, तो यह केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता का संकेत है। बीमारी न प्रशासनिक प्रक्रियाओं का इंतजार करती है, न सरकारी गति का; वह हर दिन गंभीर होती जाती है। ऐसे में 120 दिन बाद जांच की तारीख मिलना एक चिंताजनक प्रश्न खड़ा करता है–इसका बोझ आखिर कौन उठाएगा, मरीज, उसका परिवार या उसका जीवन?

एम्स भोपाल की लंबी वेटिंग लिस्ट अब केवल एक अस्पताल की समस्या नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पुरानी चुनौती का प्रतीक बन गई है। कम खर्च में बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों के लिए सस्ता इलाज भी तब बेमानी हो जाता है, जब जरूरी जांच ही महीनों बाद उपलब्ध हो। पेट के असहनीय दर्द, कैंसर की आशंका, मस्तिष्क रोग या अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज यदि केवल व्यवस्थागत कमी के कारण चार माह प्रतीक्षा करने को विवश हों, तो यह स्वास्थ्य सेवा नहीं, संवेदनहीनता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बीमारी किसी वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करती; वह लगातार बढ़ती जाती है और कई बार उपचार की संभावनाओं को भी सीमित कर देती है। विडंबना यह है कि इस व्यवस्था का सबसे बड़ा बोझ उसी वर्ग पर पड़ रहा है, जिसके नाम पर राजनीति सबसे अधिक होती है। आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति निजी अस्पताल में कुछ घंटों या दिनों में जांच करा लेता है, लेकिन मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी और निम्न मध्यमवर्गीय परिवार के लिए यह विकल्प अक्सर पहुंच से बाहर होता है। ऐसे में उसके सामने दो ही रास्ते बचते हैं–कर्ज लेकर निजी जांच कराए या दर्द और आशंका के बीच सरकारी अस्पताल की लंबी प्रतीक्षा सहे। यह केवल चिकित्सा व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता का भी दर्पण है। स्वास्थ्य सुविधाएं आय से नहीं, आवश्यकता से तय होनी चाहिए, किंतु मौजूदा व्यवस्था में पैसे वालों को समय मिलता है और अभावग्रस्तों को इंतजार। लंबी वेटिंग लिस्ट वर्षों से बढ़ती मांग और अपर्याप्त संसाधन विस्तार की कीमत है। मरीजों का बोझ बढ़ता रहा, लेकिन डॉक्टरों, विशेषज्ञों और तकनीकी कर्मचारियों की संख्या लगभग वहीं ठहरी रही।

अब यह तस्वीर बदलनी चाहिए

संजीव ठाकुर रायपुर छत्तीसगढ़,

न समय बदला,तकनीक बदली,जीवन-शैली बदली,बाजार बदला और फैशन भी बदल गया। महिलाओं को उपभोक्तावादी संस्कृति ने विज्ञापनों और प्रदर्शन की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने के नए-नए तरीके खोज लिए। किंतु दुःखद प्रश्न यह है कि क्या समाज की मूलभूत सोच बदली? क्या बालिका शिक्षा शत-प्रतिशत हो गई? क्या दहेज प्रथा समाप्त हो गई? क्या स्त्री उत्पीड़न इतिहास बन गया?दुर्भाग्य से इन प्रश्नों का उत्तर आज भी नकारात्मक है। अनेक समस्याएँ आज भी यथावत बनी हुई हैं, बल्कि कई मामलों में उन्होंने और अधिक विकराल रूप धारण कर लिया है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी अपेक्षित सम्मान और अवसरों से काफी दूर दिखाई देती है। शिक्षा,स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में सुधार तो हुआ है,किंतु वह इतना व्यापक नहीं है कि समाज को संतोष हो सके।हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि शिक्षा का प्रसार होगा तो समाज की कुरीतियाँ स्वतः समाप्त हो जाएँगी। स्त्रियाँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी और बेटी को बोझ नहीं,अवसर माना जाएगा। कुछ क्षेत्रों में प्रगति अवश्य हुई है, किंतु धरातल पर तस्वीर अभी भी अधूरी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर लगभग 46.4 प्रतिशत तक पहुँचा है, जो पहले 41 प्रतिशत था। यह सुधार उत्साहजनक है, किंतु इसका अर्थ यह भी है कि आधी से अधिक महिलाएँ अभी भी दस वर्ष की बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या आज भी चिंता का विषय बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में असमानता का एक कारण बाल विवाह, गरीबी, सामाजिक रूढ़ियाँ तथा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी हैं। अनेक परिवार आज भी पुत्र की शिक्षा को निवेश और पुत्री की शिक्षा को व्यय मानते हैं। यही सोच आगे चलकर दहेज जैसी कुप्रथा को जन्म देती और इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि शिक्षा और आधुनिकता के दावों के बीच दहेज का दानव आज भी जीवित है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत 15,489 मामले दर्ज किए गए तथा दहेज से संबंधित घटनाओं में 6,156 महिलाओं की मृत्यु हुई।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
–सम्पादक

मैनपाट के कई गांवों में पीलिया का प्रकोप...चार मौतों की चर्चा से बढ़ी चिंता

एक माह से लोग बीमार,स्वास्थ्य विभाग ने लगाए कैंप,पानी के नमूनों की जांच शुरू

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जून 2026
(घटती-घटना)।

भीषण गर्मी और बेमौसम बारिश के बीच मैनपाट क्षेत्र के नर्मदापुर, कुनिया समेत आसपास के कई गांवों में पीलिया का प्रकोप सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले एक माह से लोग सर्दी-खांसी, उल्टी और कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जांच कराने पर कई मरीजों में पीलिया की पुष्टि हुई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कुनिया के पूर्व उपसरपंच जितेंद्र यादव,नर्मदापुर निवासी भाग्यवती यादव,बैगहवा की एक युवती और बरिमा निवासी कक्षा 9 वीं के छात्र विकास यादव की मौत पीलिया के कारण हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इन मौतों को पीलिया से जोडने़ की पुष्टि नहीं की है। विभाग का कहना है कि जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। ग्रामीणों के मुताबिक बीमारी का असर करीब एक माह से बना हुआ है। कई मरीजों का इलाज अंबिकापुर और रायपुर के अस्पतालों में चल रहा है। अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज उदयभान यादव ने बताया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग पीलिया से प्रभावित हैं और कई मरीज बेहतर इलाज के लिए बाहर गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बीमारी फैलने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग समय पर सक्रिय नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि शुरुआती दौर में मरीज स्थानीय स्तर पर इलाज कराते रहे, लेकिन बीमारी बढने़ के बाद मामला सामने आया।

प्रभावित गांवों में लगाए गए कैंप

स्वास्थ्य सेवाएं, सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने मैनपाट क्षेत्र में पीलिया फैलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही विभाग को अलर्ट कर प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। टीम मरीजों की जांच और उपचार के साथ बीमारी के कारणों की भी पड़ताल कर रही है।

पानी की जांच शुरू

डॉ. शुक्ला ने बताया कि पीलिया फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए पेयजल स्रोतों की जांच कराई जा रही है। साथ ही लोगों को साफ-सफाई रखने,पानी उबालकर पीने और ताजा व गर्म भोजन करने की सलाह दी गई है।

नायब तहसीलदार तुषार मानिक राजापुर से हटाए गए,कलेक्टर कार्यालय में अटैच

विधायक समर्थकों के सरेंडर के बाद जारी हुआ आदेश,एसडीएम के तबादले की भी चर्चा...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जून 2026
(घटती-घटना)।

सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिक के बीच विवाद के बाद प्रशासनिक हलकों में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर नायब तहसीलदार तुषार मानिक को राजापुर उप तहसील से हटाकर अंबिकापुर कलेक्टर कार्यालय में अटैच कर दिया है। वहीं सीतापुर तहसीलदार उमेश बाज को राजापुर उप तहसील का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गौरतलब है कि 27 मई को विधायक की बहन द्वारा बदसलूकी का आरोप लगाए जाने के बाद नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया था। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, जिससे 1 से 3 जून तक राजस्व कार्यालयों का कामकाज प्रभावित रहा। इस बीच राजस्व मंत्री और विभागीय सचिव के साथ संघ पदाधिकारियों की चर्चा में आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद 3 जून को विधायक की पहल पर उनके दो समर्थकों ने सरेंडर कर दिया था। वहीं विधायक ने कलेक्टर से मुलाकात कर एसडीएम फागेश सिन्हा और नायब तहसीलदार तुषार मानिक को सीतापुर से हटाने की मांग की थी। नायब तहसीलदार के स्थानांतरण के बाद अब एसडीएम फागेश सिन्हा को भी सीतापुर से हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। इधर हड़ताल समाप्त होने के बाद राजस्व कार्यालयों में कामकाज सामान्य हो गया है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर ब्रह्माकुमारीज का कार्यक्रम,प्रकृति संरक्षण का दिया संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जून 2026 (घटती-घटना)।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'प्रकृति परिवर्तन' विषयक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आर्ट ऑफ लिविंग के संचालक अजय तिवारी, सिंचाई विभाग के पूर्व कार्यपालन अभियंता सुरेंद्र दुबे, वन विभाग के पूर्व रेंजर जयप्रकाश पाण्डेय, सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्माकुमारी विद्या दीदी तथा ब्रह्माकुमारी बहनों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी विद्या दीदी ने सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानव सभ्यता सदियों से प्रकृति की गोद में विकसित होती आई है। ऋषि-मुनियों ने प्रकृति के सानिध्य में आध्यात्मिक चेतना प्राप्त की और इसके सौंदर्य ने असंख्य कवियों एवं विचारकों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवनशैली और बढ़ती भौतिक आवश्यकताओं के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है तथा अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा है। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण के दो प्रमुख कारण मानसिक प्रदूषण और जीवनशैली में बदलाव को बताया। उनके अनुसार वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, उद्योगों का विस्तार,थर्मल पावर परियोजनाएं,वाहनों एवं रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों का बढ़ता उपयोग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि मानव के विचारों का प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक सोच के माध्यम से मानसिक प्रदूषण को कम किया जा सकता है। विद्या दीदी ने कहा कि संसार में तीन शक्तियां कार्य करती हैं-पुरुष (आत्मा),परम पुरुष (परमात्मा) और प्रकृति। जब आत्मा तमोप्रधान बनती है तो प्रकृति भी असंतुलित हो जाती है,जिससे प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने तथा राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से प्रकृति में सकारात्मक एवं शुद्ध ऊर्जा का संचार करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने पांच तत्वों की शुद्धि के लिए विशेष मेडिटेशन अभ्यास भी कराया। कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के संचालक अजय तिवारी ने कहा कि आज का मनुष्य बाहरी सुंदरता के प्रति अधिक आकर्षित हो रहा है, जबकि आंतरिक एवं आध्यात्मिक सुंदरता से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम प्रकृति को उससे बेहतर स्थिति में आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाएं। उन्होंने परमपिता परमात्मा शिव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पौधारोपण करने का आह्वान किया। वन विभाग के पूर्व रेंजर जयप्रकाश पाण्डेय ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए जंगलों को आग एवं मवेशियों से सुरक्षित रखने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर पर्यावरण जागरूकता से जुड़े नारे भी लगाए गए। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विकास गर्ग के फार्म हाउस, बगिया (अंबिकापुर) में भी ब्रह्माकुमारी बहनों द्वारा वृक्षारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस पर भाजपा समलाया मंडल की मासिक बैठक संपन्न,संगठ्न विस्तार और पर्यावरण संरक्षण पर हुआ मंथन

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने किया पौधारोपण,सेवा और सुशासन के कार्यक्रमों की बनाई रूपरेखा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जून 2026
(घटती-घटना)।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संकल्प भवन में भाजपा समलाया मंडल की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों,आगामी कार्यक्रमों तथा पर्यावरण संरक्षण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने सभी कार्यकर्ताओं को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रकृति संरक्षण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। अपने संबोधन में भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकारों और जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज वैश्विक चिंता का विषय है और इसे जनआंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 5 जून से 23 जून तक विभिन्न संगठनात्मक एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे,जिनके माध्यम से कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों,सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने मंडल स्तर पर व्यापक वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, 'मन की बात' कार्यक्रम, शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर की बैठकों को प्रभावी ढंग से संचालित करने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आग्रह किया। साथ ही आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक के उपरांत समलाया मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हाथी पखाना स्थित गणपति धाम पहुंचे, जहां 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। इस दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विधान चंद्राकर,मंजूषा भगत,अरुणा सिंह,डॉ. अम्बिकेश केशरी, हरमिन्दर सिंह टिन्नी, कमलेश तिवारी,अजय सोनी, अभिषेक सिंह देव,सर्वेश तिवारी,रोचक गुप्ता, शैलेन्द्र शर्मा, अर्जुन मुंडा,इंदु गुप्ता,अर्चना सिंह, नीलम रजवाड़े, अनुराधा गोस्वामी, नलनी पाण्डेय, सविता शर्मा,समीर श्रीवास्तव सहित समलाया मंडल एवं विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस की मांग पर एनएच-343 में मानकों के अनुरूप शुरू हुआ पेंच रिपेयरिंग कार्य

प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन और सांकेतिक चक्का जाम से पहले प्रशासन व एनएच विभाग ने दिखाई सक्रियता

-संवाददाता-
राजपुर,05 जून 2026
(घटती-घटना)।

राष्ट्रीय राजमार्ग-343 पर सड़क मरम्मत कार्य की गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाई गई मांग का असर दिखाई देने लगा है। प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन एवं सांकेतिक चक्का जाम से पूर्व जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) विभाग ने सकारात्मक पहल करते हुए मशीनों के माध्यम से निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पेंच रिपेयरिंग कार्य प्रारंभ करा दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लंबे समय से सड़क की खराब स्थिति और मरम्मत कार्य में गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने जनहित में आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा कार्य की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए। गुरुवार को कांग्रेस पदाधिकारियों ने क्षेत्र में चल रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों तथा ठेकेदार को कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने तथा निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सड़क मरम्मत कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता की समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को पार्टी लगातार उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कार्य में अनियमितता या लापरवाही पाई गई तो कांग्रेस पार्टी जनहित में पुनः आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। निरीक्षण के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुनील सिंह, जिला महामंत्री जितेंद्र गुप्ता, ब्लॉक उपाध्यक्ष लालसाय मिंज, किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राम बिहारी यादव, झींगों मंडल अध्यक्ष सुनील भगत, कौशल चौबे, कोषाध्यक्ष रवि सोनी, सेवा दल अध्यक्ष संतोष सोनी, पंकज ठाकुर, आलोक सिंह सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सरगुजा पुलिस का साइबर अपराधियों पर शिकंजा : म्यूल अकाउंट नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई...दो मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र,गुजरात,पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से जुड़े खातों का खुलासा,अश्लील वीडियो देखने के नाम पर महिला से 4.50 लाख की ठगी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस ने साइबर अपराध और म्यूल अकाउंट नेटवर्क के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए दो अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली और गांधीनगर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। एक मामले में विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर शिकायतों से जुड़े म्यूल खातों का संचालन करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि दूसरे मामले में महिला को गिरफ्तारी का भय दिखाकर 4.50 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में सरगुजा पुलिस द्वारा म्यूल अकाउंट, फर्जी सिम धारकों और साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय (तकनीकी सेवाएं) नवा रायपुर से प्राप्त निर्देशों के बाद जिले में ऐसे खातों और उनके संचालकों की विशेष जांच की जा रही है।

चार राज्यों से शिकायत वाले म्यूल खातों का खुलासा : कोतवाली थाना पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि सूरज कुमार कश्यप निवासी नमनाकला, अंबिकापुर के नाम पर इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में संचालित दो बैंक खाते साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे। इन खातों के विरुद्ध महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़ से साइबर पुलिस पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज थीं। पुलिस जांच में सामने आया कि इंडियन बैंक के खाता क्रमांक 7844758099 तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाता क्रमांक 60504614490 में ऑनलाइन माध्यम से कुल 2 लाख 4 हजार 200 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। प्रथम दृष्टया यह राशि साइबर ठगी से जुड़ी होने की आशंका पाई गई। प्रकरण में अपराध क्रमांक 374/2026 के तहत धारा 318(4), 317(4) एवं 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पूछताछ के दौरान सूरज कुमार ने बताया कि उसके बैंक खातों की पासबुक,चेकबुक और एटीएम कार्ड उसने धीरज सिंह के माध्यम से अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराए थे। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने धीरज सिंह (34 वर्ष), निवासी फुंडूरडिहारी बीचपारा,थाना गांधीनगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। धीरज ने स्वीकार किया कि सूरज कुमार से प्राप्त बैंक दस्तावेज उसने आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा को सौंपे थे। पुलिस के अनुसार संबंधित खातों का उपयोग भी आयुष सिन्हा द्वारा किया जा रहा था तथा ठगी की रकम से जुड़े दस्तावेज और बैंकिंग सामग्री उसके पास होने की जानकारी मिली। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने सूरज कुमार और धीरज सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस अब आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की टीकमगढ़ से दबोचे गए आरोपी भी जांच कर रही है। तकनीकी साक्ष्यों और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर पुलिस टीम को मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले रवाना किया गया। वहां से तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

महिला शिक्षिका को गिरफ्तारी का डर दिखाकर 4.50 लाख की ठगी

दूसरे मामले में थाना गांधीनगर क्षेत्र के ग्राम अजिरमा निवासी मंजूलिना किस्पोट्टा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 मार्च 2026 को स्कूल से घर लौटने के बाद उन्हें एक अज्ञात मोबाइल नंबर 919232064586 से कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके नाम से गूगल ब्राउजर पर अश्लील फोटो और वीडियो देखे जाने की शिकायत है,जो दंडनीय अपराध है और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अचानक मिली इस धमकी से महिला घबरा गई। आरोपी लगातार संपर्क में रहकर उन्हें कार्रवाई और गिरफ्तारी का भय दिखाते रहे। डर और मानसिक दबाव के कारण महिला ने अलग-अलग तारीखों में विभिन्न फोन-पे नंबरों और बैंक खातों में कई किश्तों में रकम ट्रांसफर कर दी। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर ठगी का शिकार हो चुकी हैं। कुल मिलाकर उनसे 4 लाख 50 हजार रुपए की ठगी की गई। शिकायत मिलने के बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने साइबर पुलिस पोर्टल की मदद से ट्रांजेक्शन की तकनीकी जांच शुरू की। जांच में पता चला कि पीड़िता द्वारा भेजी गई रकम भारतीय स्टेट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित विभिन्न खातों में जमा की गई और बाद में अन्य खातों में ट्रांसफर कर ऑनलाइन तथा एटीएम के माध्यम से निकाली गई।

गिरफ्तार आरोपियों में: काशीराम अहिरवार (34 वर्ष) निवासी ग्राम केनवार, थाना बड़ागांव, जिला टीकमगढ़। पन्नालाल यादव (40 वर्ष) निवासी ग्राम डुंडा,थाना बड़ागांव, जिला टीकमगढ़। अभिलाषा अहिरवार (20 वर्ष) निवासी चौपरा मोहल्ला, ग्राम जरुआ, थाना लिधौरा, जिला टीकमगढ़। शामिल हैं। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी उन बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से जुड़े पाए गए जिनका उपयोग ठगी की रकम प्राप्त करने और आगे स्थानांतरित करने में किया गया था। पूछताछ में आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश और जांच अभी जारी है।

म्यूल अकाउंट बन रहे साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार : पुलिस अधिकारियों के अनुसार साइबर अपराधी सीधे अपने खाते का उपयोग नहीं करते, बल्कि कमीशन का लालच देकर अन्य लोगों के बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक और मोबाइल सिम हासिल कर लेते हैं। इन्हीं खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। ठगी की रकम पहले इन खातों में जमा की जाती है और फिर तेजी से अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे जांच एजेंसियों को वास्तविक आरोपी तक पहुंचने में कठिनाई होती है।

इन अधिकारियों की रही महत्वपूर्ण भूमिका : कोतवाली थाना के प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी, आरक्षक लालबाबू सिंह और सैनिक संतोष पटेल की भूमिका महत्वपूर्ण रही। वहीं गांधीनगर थाना के प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, उपनिरीक्षक दिलीप दुबे, आरक्षक दीनदयाल सिंह, दिनेश यादव, सरस्वती सिंह तथा साइबर सेल के आरक्षक अमन पुरी और रमेश प्रसाद ने कार्रवाई में अहम योगदान दिया।

CMYK

खड़गवां में पशु टीकाकरण का बड़ा खेल? कागजों में 100%,गांवों में पशु बेहाल

रिकॉर्ड में टीका लग गया,पशुपालक बोले...हमारे मवेशियों तक टीम पहुंची ही नहीं...

चापा-खुरा टीकाकरण पर उठे सवाल,ऑनलाइन आंकड़े और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर

बिना टीका लगे ही भर दिए आंकड़े? खड़गवां पशु चिकित्सालय पर लगे गंभीर आरोप

पशुओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ या कागजी सफलता? खड़गवां में जांच की मांग तेज

-संवाददाता-
खड़गवां (एमसीबी),05 जून 2026 (घटती-घटना)।

पशुपालन विभाग द्वारा संचालित चापा-खुरा (एफएमडी) टीकाकरण अभियान को लेकर खड़गवां विकासखंड में गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं, विभागीय रिकॉर्ड और ऑनलाइन पोर्टल में जहां टीकाकरण अभियान को लगभग शत-प्रतिशत सफल बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई पशुपालकों का दावा है कि उनके पशुओं तक टीकाकरण दल कभी पहुंचा ही नहीं। ऐसे में विभागीय दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, क्षेत्र के ग्रामीणों और पशुपालकों का आरोप है कि कई गांवों में पशुओं का नियमित टीकाकरण नहीं किया गया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सभी पशुओं को टीकाकृत दर्शा दिया गया है, यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो मामला केवल लापरवाही का नहीं बल्कि सरकारी अभिलेखों में गलत जानकारी दर्ज किए जाने का भी हो सकता है।

रिकॉर्ड में सफलता,गांवों में सवाल

पशुपालकों का कहना है कि चापा-खुरा रोग पशुओं के लिए बेहद खतरनाक संक्रामक बीमारी है,सरकार हर वर्ष इसके नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाती है,लेकिन खड़गवां क्षेत्र के कई ग्रामीणों का दावा है कि उनके पशुओं को वर्षों से कोई टीका नहीं लगाया गया,इसके बावजूद विभागीय रिकॉर्ड में टीकाकरण पूर्ण होना कई सवालों को जन्म दे रहा है,सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पशुओं तक टीका पहुंचा ही नहीं तो ऑनलाइन पोर्टल में उनकी एंट्री किस आधार पर की गई?

15 वर्षों से जमे कर्मचारियों पर भी उठे सवाल : इस पूरे विवाद के बीच विभाग में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं,स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ कर्मचारी 15 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं,ग्रामीणों का मानना है कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ रहने से जवाबदेही कमजोर होती है और पारदर्शिता प्रभावित होती है,ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे कर्मचारियों के कार्यकाल और कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की जाए।

क्या बिना टीका लगाए ही भर दिए गए आंकड़े?

ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार टीकाकरण दल गांवों तक पहुंचे बिना ही रिपोर्ट तैयार कर देते हैं,यदि ऐसा हुआ है तो ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लग सकता है,स्थानीय पशुपालकों का कहना है कि यदि स्वतंत्र एजेंसी या प्रशासन द्वारा गांव-गांव जाकर भौतिक सत्यापन कराया जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

पूरे जिले में जांच की उठी मांग...

ग्रामीणों के बीच यह चर्चा भी है कि मामला केवल खड़गवां तक सीमित नहीं हो सकता,यदि जांच शुरू होती है तो एमसीबी जिले के अन्य विकासखंडों की स्थिति भी सामने आ सकती है,पशुपालकों का कहना है कि विभागीय आंकड़ों और वास्तविक स्थिति का मिलान कराया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने पशुओं का वास्तविक टीकाकरण हुआ और कितने केवल कागजों में दर्ज हैं।

बेजुबान पशुओं की सेहत से जुड़ा मामला

विशेषज्ञों के अनुसार चापा-खुरा रोग (एफएमडी) पशुओं में तेजी से फैलने वाली बीमारी है। यदि समय पर टीकाकरण न हो तो पशुधन को भारी नुकसान हो सकता है,ग्रामीणों का कहना है कि यदि टीकाकरण में वास्तव में लापरवाही बरती गई है तो इसका सीधा असर पशुपालकों की आय और पशुधन की सुरक्षा पर पड़ सकता है, यही कारण है कि लोग इसे केवल विभागीय मामला नहीं बल्कि पशुपालकों और बेजुबान पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय मान रहे हैं।

क्या ऑनलाइन पोर्टल की होगी जांच?

मामले में एक बड़ा सवाल यह भी है कि ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड किए गए आंकड़े किस आधार पर दर्ज किए गए? क्या प्रत्येक पशु का भौतिक सत्यापन किया गया था? क्या टीकाकरण के दौरान फोटो,टैगिंग या अन्य प्रमाण संलग्न किए गए थे? यदि जांच होती है तो संभवतः इन सभी बिंदुओं की पड़ताल की जा सकती है।

विभाग ने क्या कहा?

जब इस संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी खड़गवां जे.पी. कंवर से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा मेरे द्वारा टीकाकरण के लिए दवाई उपलब्ध कराई जाती है और मेरी जानकारी में टीकाकरण किया जा रहा है, विभागीय अधिकारी के इस बयान के बाद अब सवाल यह है कि यदि टीकाकरण किया जा रहा है तो फिर ग्रामीणों और पशुपालकों की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं?

अब प्रशासन की ओर टिकी निगाहें...

मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। पशुपालकों का कहना है कि गांव-स्तर पर सत्यापन कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जानी चाहिए,यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल आंकड़ों की गड़बड़ी नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा करेगा, फिलहाल खड़गवां में एक ही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है क्या वास्तव में सभी पशुओं का टीकाकरण हुआ है, या फिर चापा-खुरा रोग के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारी रिकॉर्ड और ऑनलाइन पोर्टल तक ही सीमित रह गई है?

अनोखी सोच संस्था ने निभाया मानवता का फर्ज

असहाय परिवार के युवक का कराया अंतिम संस्कार

पिता पहले ही गुजर चुके थे,बेटे की मौत के बाद अकेली मां पर टूटा दुखों का पहाड़

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जून 2026 (घटती-घटना)।

सामाजिक सेवा और मानवीय सरोकारों के लिए लगातार सक्रिय रहने वाली अनोखी सोच संस्था ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए एक असहाय परिवार के दुःख में सहभागी बनकर मृत युवक का पूरे विधि-विधान से अंतिम संस्कार कराया। संस्था की इस पहल की शहर में सराहना हो रही है। जानकारी के अनुसार केनाबांध निवासी राहुल गुप्ता (23 वर्ष) पिछले कुछ समय से हेपेटाइटिस-बी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनका उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था, जहां गुरुवार देर रात उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। राहुल के पिता का पूर्व में ही निधन हो चुका था और परिवार में उनकी वृद्ध मां के अलावा कोई अन्य सदस्य नहीं है। आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना भी परिवार के लिए बेहद कठिन हो गया था। राहुल के निधन की सूचना मिलने पर परिजनों ने सहायता के लिए अनोखी सोच संस्था के अध्यक्ष सूर्यप्रकाश साहू से संपर्क किया। जानकारी मिलते ही संस्था ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल सहयोग का निर्णय लिया और अंतिम संस्कार की संपूर्ण व्यवस्था अपने जिम्मे ले ली। संस्था के सदस्य शंकर घाट स्थित मुक्तिधाम पहुंचे और आवश्यक सामग्री से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए पूरे धार्मिक रीति-रिवाज एवं विधि-विधान के साथ राहुल गुप्ता का अंतिम संस्कार संपन्न कराया। अंतिम संस्कार के दौरान एक अत्यंत मार्मिक दृश्य देखने को मिला। परिवार में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं होने के कारण दिवंगत राहुल की मां ने भारी मन से स्वयं अपने पुत्र को मुखाग्नि दी। यह दृश्य वहां उपस्थित लोगों को भावुक कर गया और कई लोगों की आंखें नम हो गईं। दुःख की इस घड़ी में संस्था के सदस्यों ने शोकाकुल मां को ढांढस बंधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

इस अवसर पर संस्था के सदस्य प्रकाश साहू,पंकज चौधरी,मोती ताम्रकार, संजू चटर्जी,सुनील साहू,भोला रक्सेल, अजय ताम्रकार,चंद्रप्रताप सिंह,निशांत जायसवाल,गोपी साहू,नीरज साहू,नितेश, गजानंद साहू,लरंग मुंडा,अमित जायसवाल, राहुल शुक्ला,सौरभ दास,बनाफर केरकेट्टा, सत्यम साहू,संजय एक्का सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

जयस्तंभ चौक पर बड़ा हादसा टला : बीच सड़क में गिरा बिजली का मोटा केबल,घंटों दांव पर रही लोगों की जान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 जून 2026 (घटती-घटना)।

शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में शामिल जयस्तंभ चौक से पैलेस रोड जाने वाले मार्ग पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बिजली पोल में आग लगने के बाद अचानक एक भारी-भरकम बिजली केबल टूटकर सड़क के बीचों-बीच गिर गया। घटना के समय मार्ग पर लगातार दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही जारी थी, ऐसे में किसी भी क्षण गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पोल में अचानक चिंगारी और आग लगने के बाद मोटा केबल टूटकर सड़क पर लटक गया। केबल सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि यदि केबल में करंट प्रवाहित रहता या कोई वाहन उससे टकरा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना स्थल शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र में होने के कारण आसपास बड़ी संख्या में दुकानदार, ग्राहक और राहगीर मौजूद थे। लोगों ने तत्काल संबंधित विभाग को

सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस और विद्युत विभाग की टीम पहुंची। पुलिस ने एहतियात के तौर पर यातायात को नियंत्रित किया और लोगों को केबल से दूर रहने की सलाह दी।

स्थानीय नागरिकों ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उपभोक्ताओं से भारी-भरकम बिजली बिल और मेंटेनेंस शुल्क वसूला जाता है, लेकिन जर्जर तारों और उपकरणों की समय पर मरम्मत नहीं की जाती। लोगों का कहना है कि यदि नियमित निरीक्षण और रखरखाव किया जाता तो ऐसी खतरनाक स्थिति उत्पन्न नहीं होती। नागरिकों ने मांग की है कि शहर के पुराने और जर्जर बिजली तारों का सर्वे कर उन्हें तत्काल बदला जाए तथा इस घटना की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। फिलहाल समय रहते स्थिति नियंत्रित हो जाने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने विद्युत व्यवस्था की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

छत्तीसगढ़ शासन,जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता

जल संसाधन संभाग क्र.1,अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

eProcurement Portal:https://eproc.cgstate.gov.in

(प्रथम आमंत्रण)

निविदा सूचना क्रमांकः ...01 / व. ले.लि./2026-27 दिनांक 02.06.2026 निम्नलिखित कार्यों के लिये दिनांक 23.06.2025 (17.30 बजे) तक ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

स. क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत
1	192066	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र0-1 अम्बिकापुर कार्यालय का जीर्णोद्वार कार्य।	रू. 378.35 लाख। (जी.एस.टी. छोड़कर)

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 09.06.2026 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है।

नोटः- निविदा मे भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र. 1, अम्बिकापुर (छ.ग.) कृते - मुख्य अभियंता
हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग
अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

जी0नं0 -262701221/6

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0- /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रमेन्द्र तिवारी आ. अशोक नाथ तिवारी व अन्य निवासी ग्राम राजीवनगर रिंग रोड नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की व्यपवर्तित भूमि ग्राम गंगापुरखुर्द स्थित भूमि खसरा नंबर 225/10 रकबा हेतु भूमि को अनावेदक दीप्ती तिवारी पत्नी राकेश तिवारी निवासी ग्राम राजीवनगर रिंग रोड नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास अंकन राशि रूपये 5,50,000/- में बिक्री करने का सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10.06.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः- 18/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील
तहसीलदार
अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0- /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामभगत आ. स्व. हिरा व अन्य निवासी दर्रीपारा,अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम लक्ष्मीपुर स्थित खसरा नंबर 271/2 रकबा 0.449 हे. भूमि के नक्शा में हुये त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जॉच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 24/06/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः- 04/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील
तहसीलदार
अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0/अ-6-अ/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनुज कुमार आ. स्व. निहाल राम द्वारा मुख्तार आम आत्मा दास आ. जगमोहन दास, निवासी ग्राम केशवपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम केशवपुर स्थित खसरा नंबर 364/3 रकबा 0.885 हे. भूमि के राजस्व रिकार्ड में हुये त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जाँच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 15/06/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 13/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पद्रमुद्रा से पतमुद्रा जारी।

सील
तहसीलदार
अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0- /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनीता शुक्ला पत्नी संजीव शुक्ला निवासी ए-17, रावत रेसीडेंसी कॉलोनी मनेन्द्रगढ रोड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भगवानपुरकला स्थित भूमि खसरा नंबर 235/22 रकबा 0.016 हे0 भूमि एवं उस पर निर्मित मकान को अनावेदक अतुल कुमार दुबे आ. स्व. विजयनाथ दुबे, ममता शुक्ला पत्नी अतुल कुमार दुबे निवासी 18, रेखांकन कॉलोनी मनेन्द्रगढ रोड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास निजी कार्य हेतु रूपयो की आवश्यकता होने के कारण अंकन राशि 44,00,000/- में सौदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुंजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 17.06.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।
आज दिनांक- 25/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील
तहसीलदार
अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी, जिला-सूरपुर (छ.ग.)

रा0प्र0क्र0- 20260426020007 /ब-121/2025-26

ईश्तहार

सूरजपुर, दिनांक-26.05.2026
क्रमांक/256/वाचक/2026 -
आवेदक श्री विनीत कुमार आ. बालसाय, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम तेलईकछार, तहसील लटोरी, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) एवं पूनम चर्मकार आ. कैलाश प्रसाद चर्मकार, निवासी वार्ड नम्बर 09, नया रेल्वे कालोनी, बिजुरी, जिला अनूपपुर (म. प्र.) के द्वारा द्वितीय अनुसूची की धारा 5- विशेष विवाह अधिनियम, आशियत विवाह की सूचना, शपथ पत्र, उम्र के सत्यापन हेतु अंकूसची, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेनकार्ड की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक - 30.06.2026 को दिन के 02:00 बजे उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि अवसान पश्चात् प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया जावेगा।

आज दिनांक 26.05 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित ईश्तहार जारी किया गया।

सील
अपर कलेक्टर एवं
विशेष विवाह अधिकारी
जिला सूरजपुर (छ0ग0)

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रघुनाथ आ0 स्व0 लक्ष्मण निवासी मेण्ड्राकला थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक के अपने पिता (स्व लक्ष्मण) आ0 स्व0 लंगरा की दिनांक 05/11/2008 को स्थान निवास में हुई है।

आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है। अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी।

सील
तहसीलदार
अम्बिकापुर,सरगुजा

आंगनबाड़ी भर्ती पर उठे सवाल, कलेक्टर दरबार पहुंचीं अभ्यर्थी

अधिक अंक वालों को बाहर, कम अंक अंक वालों को चयनित करने का आरोप

पूर्व विधायक गुलाब कमरो का हमला

कहा महिला एवं बाल विकास भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है विभाग सहा नाम था कर का अड्डा बन चुका है

निष्पक्ष जांच जांच नहीं हुई तो मामला पहुंचेगा शासन स्तर तक

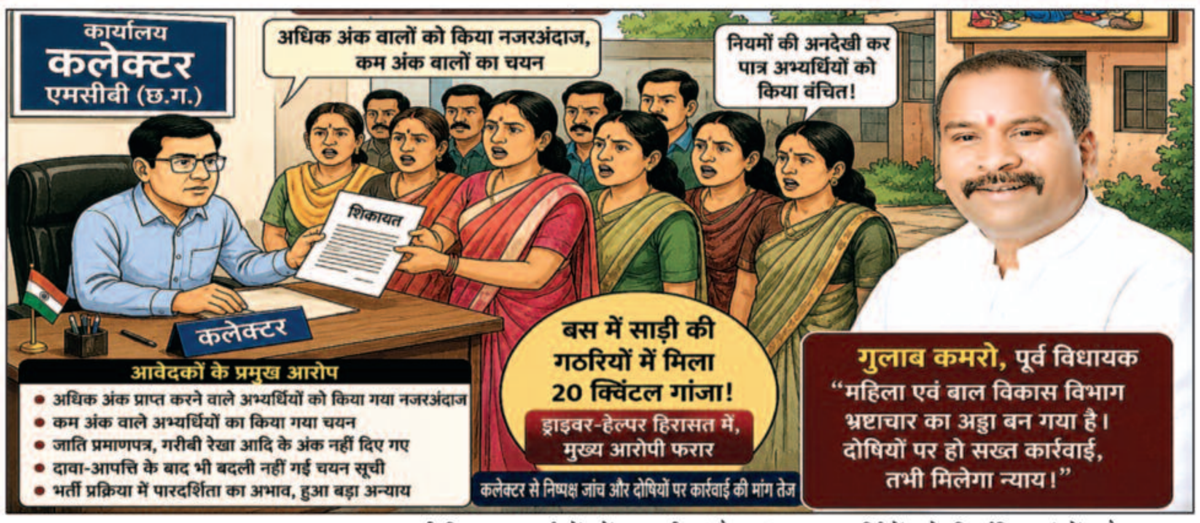

-रवि सिंह-

एमसीबी,05 जून 2026 (घटती-घटना)। जिले में हाल ही में संपन्न हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती प्रक्रिया अब विवादों के घेरे में आ गई है,भर्ती परिणाम सामने आने के बाद कई अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कलेक्टर से शिकायत की है,आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और अंक प्रणाली की अनदेखी कर प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाया गया,जबकि अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर कर दिया गया,मनेंद्रगढ़ विकासखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की,शिकायतकर्ताओं में आरती (चैनपुर), कुसुम कली (सिरौली),मीना सिंह (बुंदेली),सुमित्रा (सिरौली),रामवती (परस गढ़ी) और संजुबाई (शंकरगढ़) सहित अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं।

भर्ती प्रक्रिया पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?- शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अंतिम दावा-आपत्ति सूची जारी होने के बाद भी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई,उनका कहना है कि जिन अभ्यर्थियों को निर्धारित अंकों और पात्रता के आधार पर चयनित होना चाहिए था, उन्हें बाहर कर दिया गया, जबकि कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल कर लिया गया,आवेदकों का दावा है कि यदि निर्धारित मापदंडों का सही पालन किया जाता तो चयन सूची का स्वरूप पूरी तरह अलग होता,उनका आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से चयन किया गया है।

पूर्व विधायक गुलाब कमरो से लगाई न्याय की गुहार

भर्ती प्रक्रिया से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाब कमरो से मुलाकात कर अपनी शिकायतें रखीं,अभ्यर्थियों ने उनसे मांग की कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और प्रशासन पर निष्पक्ष जांच के लिए दबाव बनाएं,शिकायतों को सुनने के बाद पूर्व विधायक ने भी मामले को गंभीर बताते हुए जिला प्रशासन से तत्काल जांच कराने की मांग की।

अंकों की अनदेखी या चयन में खेल?

आवेदकों ने आरोप लगाया है कि कई स्थानों पर मेरिट सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति का लाभ दिया गया,उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया का मूल आधार अंक और पात्रता होती है,लेकिन यहां कथित रूप से प्रभाव,पहुंच और पक्षपात ने मेरिट को पीछे छोड़ दिया,यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो सकते हैं।

अतिरिक्त अंकों को लेकर भी विवाद

शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र,गरीबी रेखा सूची,निवास प्रमाण-पत्र और अन्य पात्रता संबंधी दस्तावेजों के आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त अंक नहीं दिए गए,उनका कहना है कि नियमों के अनुसार मिलने वाले अंक यदि जोड़े जाते तो चयन सूची का परिणाम अलग होता,इससे कई पात्र उम्मीदवार नियुक्ति पाने से वंचित रह गए, यही कारण है कि अब अभ्यर्थी केवल जांच ही नहीं बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया की पुनर्समीक्षा की मांग कर रहे हैं।

अब प्रशासन की परीक्षा

पूरा मामला अब जिला प्रशासन के पाले में है,शिकायतें कलेक्टर तक पहुंच चुकी हैं,जनप्रतिनिधि खुलकर सवाल उठा रहे हैं और प्रभावित अभ्यर्थी जांच की मांग कर रहे हैं,अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन शिकायतों की गहराई से जांच कराएगा? क्या चयन सूची और अंक सूची का पुनः परीक्षण होगा? क्या दोषियों की जवाबदेही तय होगी? या फिर यह मामला भी शिकायतों की लंबी सूची में शामिल होकर फाइलों के बीच दब जाएगा? फिलहाल मनेंद्रगढ़ विकासखंड की आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर उठे इस विवाद ने जिले में एक नई बहस छेड़ दी है और सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग भ्रष्टाचार का बन चुका है अड्डा

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने इस मामले को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग पर तीखा हमला बोला,उन्होंने कहा कि विभाग से लगातार अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं, उनके अनुसार विभाग की योजनाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का अभाव दिखाई देता है,कमरो ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना,संविदा भर्ती प्रक्रियाओं और अब आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, यदि बार-बार शिकायतें सामने आ रही हैं तो यह विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

पुरानी शिकायतों का भी दिया हवाला

पूर्व विधायक ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है,इससे पहले भी विभाग से संबंधित कई शिकायतें प्रशासन को दी गई थीं,लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई,उनका कहना है कि जब शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो लोगों का भरोसा कमजोर होता है और व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं,उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वह इस मुद्दे को शासन स्तर तक ले जाएंगे।

भर्ती प्रक्रिया पर फिर उठे भरोसे के सवाल...

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम मानी जाती है,ऐसे में यदि भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें तो इसका सीधा असर व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ता है,विशेषज्ञों का मानना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास का भी प्रश्न है, यदि चयन मेरिट के बजाय प्रभाव के आधार पर होने की धारणा बनती है तो इससे व्यवस्था की साख प्रभावित होती है।

अभ्यर्थियों की मांग क्या है?

चयन सूची की पुन : जांच कराई जाए...

मेरिट सूची और अंक सूची का सत्यापन कराया जाए...

दावा-आपत्ति प्रक्रिया की समीक्षा की जाए...

पात्रता संबंधी दस्तावेजों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए...

यदि अनियमितता मिले तो चयन प्रक्रिया निरस्त की जाए...

दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए, अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें केवल नौकरी नहीं बल्कि न्याय चाहिए....

सूरजपुर पुलिस को मिले 15 नए सब इंस्पेक्टर थानों में शुरू होगी जमीनी ट्रेनिंग

डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने जारी किया पदस्थापना आदेश

कानून-व्यवस्था,अपराध अनुसंधान और पुलिसिंग की बारीकियां सीखेंगे नए अधिकारी

-संवाददाता-

सूरजपुर,05 जून 2026 (घटती-घटना)। सूरजपुर जिले की पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 15 नव नियुक्त सब इंस्पेक्टरों (एसआई) को विभिन्न थानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए पदस्थ किया गया है,बेसिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद अब ये युवा अधिकारी पुलिसिंग के वास्तविक स्वरूप को नजदीक से समझेंगे और अनुभवी अधिकारियों के मार्गदर्शन में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं जांच संबंधी कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

डीआईजी एवं एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी नए एसआई को जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण थानों में पदस्थ किया गया है,इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नव नियुक्त अधिकारियों को जमीनी स्तर पर पुलिस कार्यप्रणाली से परिचित कराना है,ताकि भविष्य में वे अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

थानों में सीखेंगे पुलिसिंग का व्यवहारिक पक्ष

पुलिस विभाग में बेसिक प्रशिक्षण के दौरान कानून, नियम और प्रक्रियाओं की सैद्धांतिक जानकारी दी जाती है,लेकिन वास्तविक पुलिसिंग की समझ थानों में कार्य करते हुए ही विकसित होती है,इसी उद्देश्य से नए एसआई को जिले के विभिन्न थानों में भेजा गया है,जहां वे अनुभवी थाना प्रभारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्य करेंगे,इस दौरान उन्हें अपराध पंजीयन, विवेचना,कानून-व्यवस्था बनाए रखने, शिकायतों के निराकरण,सामुदायिक पुलिसिंग, गश्त व्यवस्था तथा न्यायालयीन प्रक्रियाओं की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी।

सूरजपुर थाने को मिले सबसे अधिक प्रशिक्षु एसआई

जारी आदेश के अनुसार थाना सूरजपुर में सबसे अधिक चार एसआई की पदस्थापना की गई है, वहीं थाना विश्रामपुर,जयनगर,भटगांव और प्रतापपुर में दो-दो एसआई को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है,इसके अतिरिक्त थाना प्रेमनगर,झिलमिली और रामानुजनगर में एक-एक एसआई को पदस्थ किया गया है,पुलिस विभाग का मानना है कि अलग-अलग क्षेत्रीय परिस्थितियों में काम करने से नए अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की चुनौतियों को समझने का अवसर मिलेगा।

जनता से संवाद और संवेदनशील पुलिसिंग पर रहेगा जोर

प्रशिक्षण अवधि के दौरान नव नियुक्त अधिकारियों को केवल अपराध नियंत्रण ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और संवेदनशील पुलिसिंग के गुर भी सिखाए जाएंगे,पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है कि नए अधिकारी कानून के साथ-साथ मानवीय दृष्टिकोण को भी समझें और जनता का विश्वास अर्जित करें।

पुलिस विभाग को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद

15 नए एसआई के मैदान में उतरने से जिले की पुलिस व्यवस्था को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है,इससे थानों में कार्यों का बेहतर विभाजन होगा और अपराध अनुसंधान की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी हो सकेगी,पुलिस अधिकारियों का मानना है कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अनुभव इन युवा अधिकारियों के भविष्य के कार्यकाल की मजबूत नींव साबित होगा,आने वाले समय में यही अधिकारी कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हुए जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे,अब सभी की निगाहें इन नए अधिकारियों के प्रदर्शन पर रहेंगी, जो प्रशिक्षण के दौरान सीखकर भविष्य में जिले की पुलिस व्यवस्था के मजबूत स्तंभ बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

अनुज्ञप्ति समाप्त होने के बाद भी चल रहा था संचालन,कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई...

अवैध खनिज कारोबार पर प्रशासन का बड़ा प्रहार

रामानुजनगर में दो क्रेशर संयंत्र सीलबंद,गिट्टी-बोल्डर जब्त

-संवाददाता-

सूरजपुर,05 जून 2026 (घटती-घटना)। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो क्रशर संयंत्रों को सीलबंद कर दिया है, कलेक्टर रेना जमील के निर्देश पर खनिज विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने रामानुजनगर क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर यह कार्रवाई की,प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में अवैध खनिज कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है,लंबे समय से अवैध खनिज भंडारण और बिना वैध अनुमति के संचालन की शिकायतें सामने आती रही हैं,जिसके बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

औचक निरीक्षण में खुली पोल

जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रामानुजनगर तथा खनिज विभाग सूरजपुर की संयुक्त टीम ने तहसील रामानुजनगर के विभिन्न खनिज भंडारण स्थलों और क्रशर संयंत्रों का निरीक्षण किया,निरीक्षण के दौरान ग्राम पस्ता स्थित श्रीमती सपना अग्रवाल तथा श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय के स्वामित्व वाले क्रशर संयंत्र संचालित पाए गए,दस्तावेजों की जांच में पता चला कि ग्राम छिन्दिया में स्वीकृत गौण खनिज साधारण पत्थर भंडारण अनुज्ञप्ति की वैध अवधि समाप्त हो चुकी थी, इसके बावजूद संबंधित क्रशर संयंत्रों में गतिविधियां जारी थीं,जिसे नियमों का उल्लंघन माना गया।

गिट्टी और बोल्डर किए गए जब्त

जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद संयुक्त दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों स्थलों पर भंडारित खनिज सामग्री को जब्त कर लिया। बड़ी मात्रा में गिट्टी और बोल्डर को पंचनामा तैयार कर प्रशासनिक कब्जे में लिया गया,इसके साथ ही दोनों क्रशर संयंत्रों को सीलबंद कर दिया गया ताकि बिना वैध अनुमति के आगे कोई संचालन न हो सके।

खनिज माफियाओं पर प्रशासन सख्त

जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि खनिज नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी,खनिज विभाग और जिला स्तरीय टास्क फोर्स को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं,प्रशासन का कहना है कि अवैध उत्खनन और भंडारण से न केवल शासन को राजस्व हानि होती है,बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होता है। इसलिए नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निगरानी और तेज होने के संकेत

हाल के दिनों में जिले के विभिन्न हिस्सों से अवैध खनिज परिवहन और भंडारण की शिकायतें सामने आती रही हैं,ऐसे में रामानुजनगर में हुई यह कार्रवाई अन्य संचालकों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश मानी जा रही है कि वैध अनुमति और नियमों का पालन किए बिना संचालन करना अब आसान नहीं होगा,जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध खनिज उत्खनन,परिवहन या भंडारण की जानकारी मिले तो इसकी सूचना प्रशासन को दें,ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके, फिलहाल रामानुजनगर में हुई इस कार्रवाई के बाद खनिज कारोबार से जुड़े लोगों में हलचल देखी जा रही है और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

नर्सिंग कॉलेज या फिर एक और गलत स्थल चयन? युवा नेता राजीव गुप्ता ने उठाए ऐसे सवाल, जिन पर बहस होना जरूरी

महाविद्यालय कैंपस में एसपी ऑफिस,रेस्ट हाउस में नालंदा परिसर, अब 12 किलोमीटर दूर नर्सिंग कॉलेज?

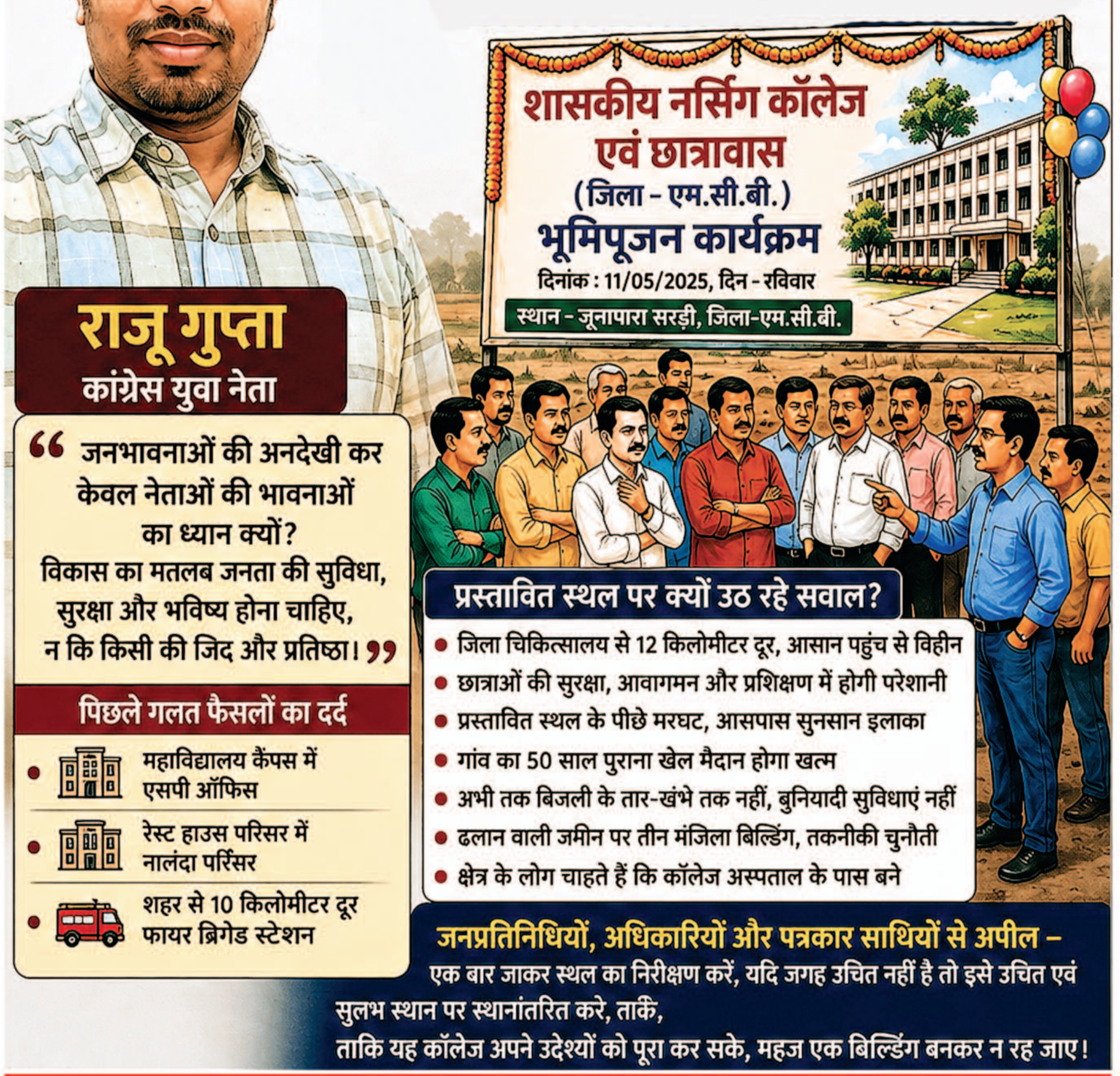

भूमिपूजन के बाद बैकुंठपुर में छिड़ी नई बहस, विकास कार्य पर नहीं बल्कि स्थान चयन पर उठ रहे सवाल

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर, 05 जून 2026 (घटती-घटना)। किसी भी जिले के लिए नर्सिंग कॉलेज का निर्माण केवल एक भवन निर्माण परियोजना नहीं होता, बल्कि यह भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था,चिकित्सा शिक्षा और स्थानीय युवाओं के रोजगार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संस्थान होता है,यही कारण है कि बैकुंठपुर में प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज और छात्रावास का भूमिपूजन होने के बाद जहां एक ओर लोग इस परियोजना का स्वागत कर रहे हैं,वहीं दूसरी ओर इसके लिए चुनी गई भूमि को लेकर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं, इन सवालों को सबसे प्रमुखता से कांग्रेस के युवा नेता राजीव गुप्ता ने उठाया है,उन्होंने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट लिखकर न केवल नर्सिंग कॉलेज के प्रस्तावित स्थल पर आपत्ति दर्ज की है,बल्कि जिले में पिछले वर्षों में लिए गए कई प्रशासनिक और राजनीतिक फैसलों को भी इस बहस से जोड़ दिया है,उनकी पोस्ट अब केवल सोशल मीडिया की चर्चा नहीं रह गई है, बल्कि बैकुंठपुर और आसपास के क्षेत्रों में जनचर्चा का विषय बन चुकी है।

अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर टिकी निगाहें...

नर्सिंग कॉलेज जिले के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है और अधिकांश लोग इसके निर्माण के पक्ष में हैं, लेकिन अब बहस इस बात पर केंद्रित हो चुकी है कि क्या चयनित भूमि वास्तव में सबसे उपयुक्त भूमि है? यदि प्रशासन के पास इसके पक्ष में मजबूत तकनीकी,भौगोलिक और शैक्षणिक तर्क हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए,वहीं यदि बेहतर विकल्प मौजूद हैं तो उन पर भी विचार किया जाना चाहिए, फिलहाल बैकुंठपुर में एक ही सवाल गूंज रहा है क्या नर्सिंग कॉलेज भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, या फिर आने वाले वर्षों में यह भी उन संस्थानों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके बारे में लोग कहते हैं इमारत तो बन गई,लेकिन जगह गलत चुन ली गई?

विकास पर नहीं,स्थान चयन पर सवाल- राजीव गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि उनका विरोध नर्सिंग कॉलेज निर्माण का नहीं है,उनका कहना है कि जिले को नर्सिंग कॉलेज मिलना एक बड़ी उपलब्धि है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए,लेकिन उनका सवाल यह है कि आखिर ऐसा महत्वपूर्ण संस्थान ऐसी जगह क्यों बनाया जा रहा है,जहां पहुंचना ही कठिन हो, जहां से जिला अस्पताल लगभग 12 किलोमीटर दूर हो और जहां छात्राओं की सुरक्षा तथा आवागमन को लेकर गंभीर चिंताएं मौजूद हों,उनका तर्क है कि यदि नर्सिंग कॉलेज का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा देना और छात्रों को अस्पताल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है,तो उसका जिला अस्पताल के आसपास होना ज्यादा व्यावहारिक और उपयोगी होगा।

जूनापारा-सरड़ी की जमीन पर उठे सवाल

राजीव गुप्ता के अनुसार प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज का स्थल शिवपुर से लगे जूनापारा-सरड़ी क्षेत्र में स्थित है, उन्होंने दावा किया है कि यह स्थान आबादी से दूर, अपेक्षाकृत सुनसान और सुविधाओं से वंचित है,उन्होंने सवाल उठाया कि जिस संस्थान में बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन करेंगी, उनके लिए सुरक्षित और सुगम पहुंच वाला स्थान अधिक उपयुक्त होना चाहिए, उन्होंने यह भी कहा कि जिस जगह का चयन किया गया है,वहां अभी तक बुनियादी सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, ऐसे में आने वाले वर्षों में कॉलेज संचालन को लेकर भी व्यावहारिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

50 साल पुराने खेल मैदान पर संकट

विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू खेल मैदान को लेकर सामने आया है,ग्रामीणों का दावा है कि जिस भूमि का चयन नर्सिंग कॉलेज निर्माण के लिए किया गया है,वहां पिछले लगभग 50 वर्षों से खेल गतिविधियां संचालित होती रही हैं,आसपास के गांवों के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए यही प्रमुख खेल मैदान है,स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि वर्तमान समय में युवाओं को खेलों से जोड़ने की आवश्यकता है। ऐसे समय में यदि क्षेत्र का एकमात्र बड़ा मैदान समाप्त हो जाता है तो इसका सीधा असर ग्रामीण खेल संस्कृति पर पड़ेगा, ग्रामीणों ने मांग की है कि नर्सिंग कॉलेज के लिए किसी अन्य उपयुक्त भूमि का चयन किया जाए और खेल मैदान को सुरक्षित रखा जाए।

पीछे मरघट,सामने कॉलेज–भावनात्मक और सामाजिक सवाल

राजीव गुप्ता की पोस्ट का एक हिस्सा स्थानीय लोगों के बीच विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है,उन्होंने उल्लेख किया कि प्रस्तावित स्थल के पीछे श्मशान भूमि स्थित है,हालांकि तकनीकी दृष्टि से यह निर्माण में बाधा नहीं हो सकती,लेकिन स्थानीय लोगों की भावनाओं और सामाजिक दृष्टिकोण से इसे लेकर आपत्तियां सामने आ रही हैं,ग्रामीणों का कहना है कि इतने बड़े शैक्षणिक संस्थान के लिए और भी बेहतर विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

खेल मैदान बचाने की मांग...

विवाद का दूसरा बड़ा पहलू खेल मैदान को लेकर सामने आया है,स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि जिस भूमि का चयन किया गया है,वह पिछले कई दशकों से क्षेत्र के युवाओं का प्रमुख खेल मैदान रहा है,राजू गुप्ता ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मोबाइल और सोशल मीडिया के इस दौर में जहां युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है,वहां यदि क्षेत्र का एकमात्र बड़ा खेल मैदान समाप्त हो जाता है तो इसका सीधा असर खेल गतिविधियों पर पड़ेगा, ग्रामीणों का भी कहना है कि यदि नर्सिंग कॉलेज बनाना है तो किसी वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए,ताकि खेल मैदान भी सुरक्षित रहे और कॉलेज भी बन सके।

जिला अस्पताल से दूरी क्यों चिंता का विषय है?

नर्सिंग शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अस्पतालों में व्यावहारिक प्रशिक्षण होता है, विशेषज्ञों का मानना है कि नर्सिंग छात्रों को नियमित रूप से अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, चिकित्सा प्रक्रियाओं और आपातकालीन परिस्थितियों का प्रशिक्षण लेना पड़ता है, राजू गुप्ता का कहना है कि यदि कॉलेज जिला अस्पताल से 12 किलोमीटर दूर होगा तो छात्रों को प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, इससे समय,संसाधन और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं,उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि किसी आपातकालीन स्थिति में यदि नर्सिंग छात्राओं की आवश्यकता पड़े तो इतनी दूरी एक बड़ी बाधा बन सकती है।

पुराने फैसलों का जिक्र क्यों?

अपनी पोस्ट में राजीव गुप्ता ने केवल नर्सिंग कॉलेज की बात नहीं की,उन्होंने जिले में पूर्व में लिए गए कुछ फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि बैकुंठपुर पहले भी गलत स्थल चयन की कीमत चुका चुका है,उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महाविद्यालय परिसर में एसपी कार्यालय स्थापित किया गया,रेस्ट हाउस परिसर में नालंदा परिसर बनाया गया और फायर ब्रिगेड स्टेशन शहर से काफी दूर स्थापित किया गया,उनका आरोप है कि इन फैसलों को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं और अब नर्सिंग कॉलेज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी बनता दिखाई दे रहा है।

क्या यह विकास है या प्रतिष्ठा का प्रश्न?

राजीव गुप्ता ने अपने पोस्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है,उन्होंने कहा कि यदि चयनित भूमि वास्तव में उपयुक्त नहीं है तो इसे किसी की प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए,उनका कहना है कि विकास परियोजनाओं का उद्देश्य जनता को सुविधा देना होता है, न कि किसी निर्णय को हर हाल में सही साबित करना,उन्होंने जनप्रतिनिधियों,अधिकारियों और पत्रकारों से अपील की है कि वे स्वयं स्थल का निरीक्षण करें और निष्पक्ष रूप से तय करें कि यह स्थान वास्तव में नर्सिंग कॉलेज के लिए उपयुक्त है या नहीं।

सवाल विपक्ष से भी...

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुद्दा केवल नर्सिंग कॉलेज का नहीं बल्कि स्थानीय विकास मॉडल का प्रश्न बनता जा रहा है,दिलचस्प बात यह है कि जिन सवालों को संगठित विपक्ष को उठाना चाहिए था,वे सवाल एक युवा नेता ने सोशल मीडिया के माध्यम से उठा दिए, अब यह देखना होगा कि कांग्रेस संगठन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस बहस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

न्यायालय परिसर में हरियाली का संकल्प,विश्व पर्यावरण दिवस पर न्यायाधीशों ने किया वृक्षारोपण

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,05 जून 2026 (घटती-घटना)। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायालय बैकुंठपुर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण,प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम का नेतृत्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश पारीक ने किया,उन्होंने न्यायालय परिसर में पौधारोपण कर उपस्थित अधिकारियों,कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह प्रकृति के संरक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे,यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश आशीष पाठक,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक्षा अग्रवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अमृता दिनेश मिश्रा तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुल्तान अंसारी ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण,जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण पर्यावरणीय चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं,ऐसे समय में वृक्षारोपण केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है,उन्होंने सभी नागरिकों से पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी देखभाल करने का भी आह्वान किया।

कार्यक्रम में न्यायालय के सभी न्यायाधीशगण, कर्मचारीगण तथा जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, सभी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने तथा अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया,विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम ने न्यायालय परिसर को हरियाली से जोड़ने के साथ-साथ समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक संदेश प्रसारित करने का कार्य किया,वृक्षारोपण के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रकृति के संरक्षण के बिना सतत विकास की कल्पना संभव नहीं है।

बिजली की बदहाली और सड़क सुरक्षा को लेकर फूटा जनाक्रोश

बैकुंठपुर के नागरिकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, समस्याओं के समाधान की उठाई मांग

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,05 जून 2026 (घटती-घटना)। जिला मुख्यालय बैकुंठपुर सहित पूरे जिले में बिजली व्यवस्था की खराब स्थिति,सड़क सुरक्षा की अनदेखी और बढ़ती यातायात समस्याओं को लेकर नागरिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है,ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आम जनता आंदोलन के लिए मजबूर होगी।

जर्जर तार और बिजली कटौती से जनता परेशान

ज्ञापन में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। नागरिकों का कहना है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति लगातार प्रभावित हो रही है, ट्रांसफार्मरों पर बढ़ते लोड के कारण आए दिन उपकरण जलने और बिजली बाधित होने की समस्या सामने आ रही है,लोगों ने मांग की है कि पुराने ट्रांसफार्मरों को बदलकर अधिक क्षमता वाले नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। साथ ही शहर के मुख्य मार्गों पर लटक रहे जर्जर बिजली तारों को हटाकर सुरक्षित केबल लगाए जाएं, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका समाप्त हो सके।

मेंटेनेंस के नाम पर अघोषित कटौती पर सवाल

शहरवासियों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर बार-बार बिजली बंद करता है,लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम दिखाई नहीं देता, बिना सूचना के होने वाली कटौती से लोगों को भारी परेशानी होती है, नागरिकों ने मांग की है कि विभाग मेंटेनेंस कार्यों की सार्वजनिक जानकारी जारी करे और शिकायतों के लिए 24 घंटे संचालित टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू करे,क्योंकि संकट के समय विभागीय फोन तक नहीं उठाए जाते।

गेज नदी पुल बना दुर्घटनाओं का खतरा

ज्ञापन में गेज नदी पुल की खतरनाक स्थिति को भी प्रमुखता से उठाया गया है, स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने और नए पुल के जोड़ के कारण सड़क का हिस्सा टेढ़ा हो गया है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है, नागरिकों ने पुल के दोनों ओर हाई विजिबिलिटी रेडियम बोर्ड लगाने तथा पुल और सड़क के जोड़ वाले हिस्से का स्थायी तकनीकी समाधान करने की मांग की है,उनका कहना है कि बार-बार किए जाने वाले पैचवर्क से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

एसईसीएल मैदान को कार्यक्रमों के लिए विकसित करने का सुझाव

शहर में बड़े आयोजनों के दौरान ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या को देखते हुए नागरिकों ने खाली पड़े एसईसीएल मैदान को सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए विकसित करने का सुझाव दिया है,उनका मानना है कि इससे रामानुज विद्यालय मैदान पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकेगा और शहर में यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी।

कलेक्टर ने दिया सकारात्मक आश्वासन

ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को जिला कलेक्टर ने समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है,नागरिकों का कहना है कि अब समय केवल आश्वासनों का नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाने का है,इस दौरान समाजसेवक एवं साहित्यकार संवर्त कुमार रूप,मंडल अध्यक्ष अनिल खटीक,पार्षद मनीष कुमार सिंह, पार्षद अभिनेंद्र सिंह चंदेल,शहीद अशरफी तथा महेंद्र सिंह सहित अन्य नागरिक उपस्थित रहे।

पेद्दी की बंपर ओपनिंग पर राम चरण की बेटर हाफ ने किया ग्रैंड सेलिब्रेशन

राम चरण स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और पहले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सेंचुरी मार दी है। तेलुगु एक्टर राम चरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म पेद्दी 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफ़िस पर इसकी शुरुआत जबरदस्त रही। क्रिटिक्स और दर्शकों से मिले मिले-जुले से लेकर अच्छे रिव्यूज़ के बावजूद, इस स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म ने शानदार ओपनिंग की है और पहले ही दिन दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फ़िल्म की जबरदस्त ओपनिंग के बीच,राम चरण की पत्नी और एंटरप्रेन्योर उपासना कोनिडेला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह फैन्स के साथ इस कामयाबी का जश्न मना रही हैं।

उपासना ने किया ग्रैंड सेलिब्रेशन

वीडियो में उपासना एक बड़ा कस्टमाइज़्ड केक काटती हुई दिख रही हैं, जिस पर फिल्म का पोस्टर और पेद्दी ब्लकबस्टर लिखा है। केक पर पांच स्टार भी बने हैं, जो दर्शकों से फिल्म को मिले अच्छे रिस्पॉन्स को दिखाते हैं। पिंक कुर्ते-सेट में उपासना बहुत खुश नजर आ रही हैं और फ़ैन्स व शुभचिंतकों के साथ इस मौके का जश्न मना रही हैं।
वीडियो में आगे दिखाया गया कि फैन फिल्म की सफलता का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़ रहे थे। उपासना को जश्न में मौजूद बच्चों से बातचीत करते और उन्हें केक खिलाते हुए भी देखा गया। उनके आस-पास जमा कई लोगों ने तालियाँ बजाई और उत्साह बढ़ाया, जबकि जश्न जारी रहा।

फैंस के साथ उपासना ने देखी पति की फिल्म

यह पहली बार नहीं है जब उपासना को राम चरण की नई फ्ल्मि को सपोर्ट करते हुए देखा गया है। इससे पहले, हैदराबाद के एक थिएटर में फैन के साथ पेद्दी देखते हुए उनका एक और वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ था। वह फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान दर्शकों के साथ शामिल हुईं और राम चरण के सीन के लिए उत्साहपूर्वक चीयर करती दिखीं।

सेलिना जेटली का बड़ा बयान

कानूनी नोटिसों पर दी कड़ी प्रतिक्रिया

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके पति पीटर हाग से तलाक और बच्चों की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद ने मीडिया का ध्यान खींचा हुआ है। इस बीच, सेलिना ने अपने पति और ससुर की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिसों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। सेलिना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की कानूनी धमकी या दबाव के आगे झुकने वाली नहीं हैं। उन्होंने साफ किया कि वह अपने बच्चों, अपने अधिकारों और न्याय के लिए पूरी तरह लड़ाई जारी रखेंगी। अभिनेत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि इस कठिन समय में उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा और भले के लिए हर कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने मूल अधिकारों और बच्चों के हितों से समझौता नहीं करेंगी। पिछले कुछ महीनों से सेलिना और पीटर के बीच तलाक और कस्टडी के मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। कानूनी नोटिसों के बाद अब सेलिना ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए मीडिया और फैंस के सामने सच्चाई और अपनी मजबूती पेश की है।

ईशा देओल ने किया बंदर का रिव्यू,

भैया बॉबी देओल की परफॉर्मेंस पर बोलीं- आज के बेहतरीन एक्टर.बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की फिल्म बंदर आखिरकार 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रिलीज से पहले, उनकी कजिन और एक्ट्रेस ईशा देओल गुरुवार को मुंबई में फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुईं। स्क्रीनिंग के बाद, ईशा ने सोशल मीडिया पर बॉबी की परफॉर्मेंस की तारीफ की और दर्शकों से फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की अपील की।

ईशा ने की बॉबी की तारीफ

गुरुवार को ईशा ने इंस्टाग्राम पर बॉबी देओल और तान्या देओल के साथ एक तस्वीर शेयर की। अपने भाई की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा,आप अब तक के सबसे बेहतरीन फॉर्म में हैं! बेशक,आज के सबसे बेहतरीन एक्टर। मजबूत और संवेदनशील! बहुत बढ़िया,भैया। उन्होंने फैन्स से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा, जाकर बंदर जरूर देखें। बाद में बॉबी ने इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर री-शेयर किया। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी बंदर एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है,जिसे निखिल द्विवेदी ने अपने बैनर सैफ्रन मैजिक वर्क्स के तहत प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की कहानी सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखी है और यह असल जिंदगी की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं,जबकि सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी,सबा आजाद, इंद्रजीत सुकुमारन, राज बी. शेट्टी और जितेंद्र जोशी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं।

क्या है फिल्म की कहानी?

बंदर फिल्म एक उम्रदराज टेलीविजन स्टार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिस पर उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड ने रेप का आरोप लगाया है। इस फिल्म का प्रीमियर 6 सितंबर, 2025 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फ़ेस्टिवल के स्पेशल प्रेजेंटेशन्स सेक्शन में हुआ था। यह बॉबी देओल और अनुराग कश्यप के बीच पहला सहयोग भी है। फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू मिले हैं। कई लोगों ने बॉबी की परफॉर्मेंस की तारीफ की है और इसे उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक बताया है।

बॉबी देओल का वर्कफ्रंट

बंदर के बाद, बॉबी वाईआरएफस्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा में नजर आएंगे। शिव रवैल के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में आलिया भट्ट,शरवरी और अनिल कपूर अहम भूमिकाओं में हैं। अल्फा यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की सातवीं फिल्म है, जिसमें एक था टाइगर,टाइगर जिंदा है,वॉर,पठान,टाइगर 3 और वॉर 2 शामिल हैं।

एक गाना,कई दौर:‘तूतक तूतक तूतिया’ की हिट जर्नी

साल 1989 में आई फिल्म ‘घर का चिराग’ का एक गाना ‘तूतक तूतक तूतिया,आई लव यू’ उस समय काफी हिट हुआ था। इस गाने ने लोगों के बीच खूब लोकप्रियता हासिल की थी और इसे डांस और म्यूजिक प्रोग्राम्स में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। हालांकि,उस समय भी और आज भी बहुत से लोगों को इस गाने के शब्दों का सही मतलब पता नहीं था। यह गाना अपनी अलग धुन और मस्ती भरे अंदाज के कारण लोगों के बीच तेजी से फैल गया। बच्चों से लेकर युवाओं तक,सभी ने इस गाने पर डांस किया और इसे खूब गुनगुनाया। इसकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि विदेशों में भी भारतीय म्यूजिक प्रेमियों के बीच इस गाने ने अपनी जगह बनाई। इसके बाद साल 2016 में इस गाने का एक नया वर्जन फिल्म ‘देवी’ में देखने को मिला। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया और सोनू सूद मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस नए वर्जन ने भी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा। इस गाने को फिर से कनिका मान और मलकीत सिंह ने अपनी आवाज दी थी। खास बात यह है कि यह गाना मूल रूप से मलकीत सिंह का ही है और उन्होंने ही इसे लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मलकीत सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस गाने में इस्तेमाल किए गए शब्दों का कोई सीधा अर्थ नहीं है, बल्कि यह एक तरह की लय और मनोरंजन के लिए बनाए गए शब्द हैं,जो सुनने में मजेदार लगते हैं। संगीत विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के गाने अपनी सरल धुन और दोहराव के कारण जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं। ‘तूतक तूतक तूतिया’ भी उन्हीं गानों में से एक है, जिसने समय-समय पर नई पीढ़ी को भी आकर्षित किया है। आज भी यह गाना शादी, पार्टी और स्टेज शो में खूब बजाया जाता है और लोग इस पर जमकर डांस करते हैं। इसका रीमिक्स वर्जन आने के बाद इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। कुल मिलाकर, ‘तूतक तूतक तूतिया’ एक ऐसा गाना है जिसने 1989 से लेकर 2016 तक और उसके बाद भी अपनी पहचान बनाए रखी है और आज भी यह लोगों के बीच मनोरंजन का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है।

है जवानी तो इश्क होना है एक्स रिव्यू

किसी को लगी धांसू,तो किसी के निकले आंसू;दर्शकों ने किया वरुण की फिल्म का रिव्यू है जवानी तो इश्क होना है एक्स रिव्यू : वरुण धवन और मृणाल ठाकुर की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के आज रिलीज होने के साथ ही,फिल्म के बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया और राय वरुण धवन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के साथ बड़े पर्दे पर जबरदस्त वापसी कर रहे हैं,जो 5 जून,2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बॉर्डर 2के बाद यह इस साल धवन की दूसरी फिल्म होगी और भारत में हिंदी फिल्मों के शौकीनों के बीच इसे लेकर पहले से ही काफी चर्चा है।

डेविड धवन की आखिरी फिल्म

डेविड धवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि कहा जा रहा है कि यह अनुभवी निर्देशक का आखिरी प्रोजेक्ट होगा, जिससे दर्शकों में इसे लेकर और भी ज्यादा उत्सुकता है। यह फिल्म वरुण धवन और उनके पिता के बीच चौथी बार का सहयोग है; इससे पहले वे मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2,और कुली नंबर 1 जैसी सफल फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं।

है जवानी तो इश्क होना पर दर्शकों का रिव्यू

डेविड धवन के निर्देशन और वरुण धवन की स्टार पावर के मेल ने फिल्म की रिलीज से पहले ही काफी चर्चा पैदा कर दी थी। वहीं अब दर्शकों ने भी फिल्म पर अपनी राय शेयर कर दी है।

खेल समाचार

अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू करेंगे हर्ष दुबे और मानव सुथार?

अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम 6 जून से टेस्ट मैच खेलेगी...इस मैच में भारत के लिए मानव सुथार और हर्ष दुबे डेब्यू कर सकते हैं...टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने इसे लेकर इशारा दिया है...

न्यू चंडीगढ़,05 जून 2026। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में दो अनकैप्ड स्पिनर गेंदबाजों को जगह मिली है। इसमें मानव सुथार के साथ हर्ष दुबे शामिल हैं। भारत के पास रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में टेस्ट में तीन प्रमुख स्पिनर हैं। टीम को चौथे स्पिनर की तलाश है। इसके लिए मानव सुथार और हर्ष दुबे के बीच टक्कर है। 6 जून से भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच है।

श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया का फोकस

भारतीय टीम को अगस्त में श्रीलंका दौरे पर टेस्ट खेलना है। टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि भारत को श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए स्पिन गेंदबाजी के कई विकल्प तैयार करने होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘मानव और हर्ष कुछ हद तक एक जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके गेंद फेंकने के तरीके में कुछ अंतर भी हैं। आप सिर्फ ये नहीं देखते कि दो लेफ्ट-आर्म स्पिनर हैं बल्कि ये भी देखते हैं कि गेंद छोड़ने का पॉइंट क्या है, विकेट से गेंद को क्या मदद मिल रही है और गेंद की ट्रैजेक्टरी कैसी है। ये भी कि कौन रेड-बॉल क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा।

गौतम गंभीर ने आगे कहा- शायद ये इकलौता ऐसा टेस्ट मैच है जहां हम चौथे स्पिनर के तौर पर किसी को आजमाने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि इसके बाद हम श्रीलंका जाएंगे और हो सकता है कि हमें चार स्पिनर साथ ले जाने पड़ें। इसलिए,ये किसी ऐसे खिलाड़ी को आजमाने का सही मौका है जो लंबे समय तक चौथा स्पिनर बन सके।
हमें पता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम शायद अपने फिंगर स्पिनर को मौका देने के बारे में सोच सकते हैं, जो चौथा स्पिनर भी हो सकता है। आखिर टेस्ट मैच तो टेस्ट मैच ही होता है। मुझे पता है कि लोग कह सकते हैं कि यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसा टेस्ट मैच है जिसे हमें देश के लिए जीतना है।आप टेस्ट मैचों के बीच कोई फर्क नहीं करते, चाहे वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हो या न हो।

हर्ष दुबे और मानव सुथार के रिकॉर्ड

23 साल के हर्ष दुबे विदर्भ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 27 फर्स्ट क्लास मैच में उनके नाम 133 विकेट और 1026 रन हैं। इसमें 9 फिफ्टी शामिल है। वह 9 बार पारी में 5 विकेट लेने के साथ ही 2 बार मैच में 10 विकेट ले चुके हैं। राजस्थान के मानव सुथार के नाम 29 फर्स्ट क्लास मैचों में 129 विकेट और 925 रन हैं। वह एक शतक और 6 फिफ्टी मार चुके हैं। मानव ने 6 बार पारी में 5 विकेट और तीन बार मैच में 10 विकेट ले चुके हैं। दोनों बाएं हाथ के स्पिनर और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं।

रुमेश पथिरागे ने डायमंड लीग का खिताब जीता

भारत के सचिन यादव आठवें स्थान पर रहे...

रोम ,05 जून 2026। रोम डायमंड लीग 2026 में पुरुषों का जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) खिताब जीतने के दौरान श्रीलंका के रुमेश पथिराज, ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के एशियाई रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच गए। पथिराज ने स्टैडियो ओलिम्पिको में 92.62 मीटर का शानदार थ्रो किया। यह दूरी नदीम के एशियाई रिकॉर्ड और पेरिस 2024 गेम्स में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले थ्रो से सिर्फ़ 35 सेंटीमीटर कम थी। 23 साल के एथलीट का यह शानदार प्रदर्शन उनके पिछले सबसे अच्छे रिकॉर्ड (89.37 मीटर) से काफी बेहतर था, जो उन्होंने मार्च में एक घरेलू प्रतियोगिता में बनाया था। उन्होंने अगले महीने नैरोबी में एक मीट में 89.28 मीटर का थ्रो करके 89 मीटर का आंकड़ा भी पार किया था, जो इस इवेंट में उनकी तेज़ी से होती तरक्की को दिखाता है। रोम में, पथिराज ने अपने दूसरे प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की, जबकि पहले प्रयास में उन्होंने 84.49 मीटर की दूरी तय की थी। इस कारनामे के साथ,श्रीलंकाई एथलीट जैवलिन थ्रो में 90 मीटर की दूरी पार करने वाले चौथे एशियाई एथलीट बन गए। उनसे पहले चीनी ताइपे के चेंग चाओ-त्सुन (91.36 मीटर), भारत के ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा (90.23 मीटर) और पाकिस्तान के अरशद नदीम (जिन्होंने अपने करियर में कई बार यह दूरी पार की है) ऐसा कर चुके हैं। इस प्रदर्शन ने नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसेन द्वारा 2006 में बनाए गए 90.34 मीटर के 20 साल पुराने मीट रिकॉर्ड को भी 2.28 मीटर के बड़े अंतर से तोड़ दिया।

गुराशिश सिंह और प्रतीक भौंत एशियन गेम्स 2026 के लिए चयनित

मुंबई,05 जून 2026। एस8यूएल ईस्पोर्ट्स के फाइटिंग गेम एथलीट गुरशीश सिंह (सोल) और प्रतीक भौंट (बी हॉन्ट) ने एशियाई खेल 2026 में क्रमशः टेकेन 8 और स्ट्रीट फाइटर 6 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालीफाई कर लिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों खिलाड़ियों ने नेशनल ईस्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में अपने-अपने इवेंट जीतकर अपनी जगह पक्की की, जो खेलों में भारत के ईस्पोर्ट्स दल के लिए आधिकारिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट है। सोल, जिन्होंने इससे पहले ब्रिक्स ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, टेकेन 8 में राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में उभरे,जबकि बी हॉन्ट ने स्ट्रीट फाइटर 6 में शीर्ष सम्मान हासिल करके टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर ली। उनकी सफलता भारत के बढ़ते फाइटिंग गेम समुदाय के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है और जमीनी स्तर पर प्रतिभा विकास के निवेश के प्रभाव को दर्शाती है। दोनों खिलाड़ी एस8यूएल गौंटलेट के माध्यम से संगठन में शामिल हुए, जो अपनी तरह का पहला फाइटिंग गेम्स टैलेंट हंट प्रोग्राम है जिसे भारत के कुछ सबसे होनहार खिलाड़ियों की पहचान करने, उनका समर्थन करने और उन्हें विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

चीन ने एशिया कप 2026 फाइनल में जगह बनाई

काकामिगाहारा ,05 जून 2026। शुक्रवार को जापान के काकामिगाहारा में 18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में, चार क्वार्टर तक चले कड़े और रोमांचक मैच के 2-2 से ड्रॉ रहने के बाद, भारतीय 18 महिला हॉकी टीम को चीन के खिलाफ शूटआउट में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा।भारत के लिए नौशीन नाज़ (3%) और किरण एक्का (54%) ने गोल किए, जबकि चीन के लिए ली ज़ेयान (24%) और झांग युज़ेंग (48%) ने गोल किए। भारत ने पहले क्वार्टर में शानदार शुरुआत की और तीसरे मिनट में ही पहला गोल कर दिया। कप्तान स्वीटी कुजुर ने मिडफील्ड से सर्कल के अंदर नौशीन (3%) को एक बेहतरीन पास दिया,जिन्होंने ज़ोरदार बैक-हैंड शॉट से नेट में गोल करके भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों टीमों ने मिडफील्ड में अच्छा खेल दिखाते हुए सर्कल के अंदर अच्छे मौके बनाए, लेकिन पहले क्वार्टर में कोई और गोल नहीं हो सका। चीन को 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन फेंग जियाक्सिन के ड्रैग-फ्लिक को भारतीय गोलकीपर महक परिहार ने शानदार ढंग से रोक दिया। हालाँकि,तीन मिनट बाद, 24वें मिनट में भारत की डिफेंसिव गलती का फायदा उठाते हुए चीन ने बराबरी का गोल किया; चीन की ली ज़ेयान ने फील्ड गोल करके स्कोर बराबर कर दिया।

रायगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 300 किलो गांजा बरामद,तीन अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

दो लग्जरी वाहनों समेत 1.86 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त,तस्करी नेटवर्क की जांच तेज

रायगढ़,05 जून 2026। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लैलूंगा पुलिस ने उड़ीसा से मध्यप्रदेश ले जाई जा रही करीब 300 किलोग्राम गांजा की खेप जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान दो लग्जरी वाहन और मोबाइल फोन सहित कुल 1 करोड़ 86 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, उड़ीसा के सोनपुर क्षेत्र से भारी मात्रा में गांजा मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले भेजे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर लैलूंगा पुलिस ने विभिन्न मार्गों पर नाकेबंदी कर सघन जांच अभियान शुरू किया। कटकलिया मार्ग पर घेराबंदी के दौरान एक इनोवा क्रिस्टा और मारुति सुजुकी एक्सएल-6 को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान इनोवा वाहन में दो अलग-अलग नंबर प्लेट लगी मिलीं, जिससे पुलिस का संदेह और गहरा गया। तलाशी लेने पर दोनों वाहनों से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों वाहनों से कुल लगभग 300 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी बाजार कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही इनोवा क्रिस्टा, मारुति एक्सएल-6 और पांच मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। कुल जब्ती की कीमत लगभग 1.86 करोड़ रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निखिल कश्यप निवासी बलरामपुर, रिंकु कश्यप निवासी सरगुजा तथा धर्मेन्द्र कुमार मौर्य निवासी अनूपपुर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ में आरोपियों ने गांजा की खेप मध्यप्रदेश के अनूपपुर में अपने सहयोगियों तक पहुंचाने की जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस ने पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाने के लिए विशेष टीम को मध्यप्रदेश और सरगुजा क्षेत्र में रवाना किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी

अफेयर के शक में बाउंसर के आंख में मिर्च पावडर डालकर उतारा मौत के घाट,आरोपी फरार

बिलासपुर,05 जून 2026। जिले के कोटा थाना क्षेत्र के पथर्रा गांव में कथित प्रेम प्रसंग और चरित्र शंका ने एक युवक की जान ले ली। 27 वर्षीय बाउंसर निखिल गोस्वामी की पहले आंखों में मिर्च पाउडर डालकर हमला किया गया, फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार, निखिल गोस्वामी बिलासपुर के एक बार में बाउंसर के रूप में कार्यरत था। बुधवार रात वह अपने दो दोस्तों के साथ अमने मोड़ के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान बाइक सवार तीन-चार युवक वहां पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, उनमें से एक को पहचानकर निखिल ने आवाज लगाई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि भोला मानिकपुरी और उसके साथियों ने पहले निखिल की आंखों और चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। अचानक हुए हमले से वह कुछ समझ पाता, उससे पहले उसके साथ मौजूद दोनों साथी वहां से भाग निकले। इसके बाद हमलावरों ने निखिल को निशाना बनाते हुए पास में पड़े भारी पत्थर से उसके सिर और शरीर पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल निखिल को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी मधुलिका सिंह और कोटा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी भोला मानिकपुरी को अपनी पत्नी और निखिल के बीच कथित संबंधों का शक था। इसी वजह से दोनों के बीच लंबे समय से तनाव और विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग, पुरानी रंजिश और चरित्र शंका सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मुख्य आरोपी भोला मानिकपुरी समेत अन्य संदिग्ध वारदात के बाद से फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

आत्मानंद स्कूलों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बनेंगे 108 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्राइवेट स्कूलों जैसी मिलेगी सुविधा

रायपुर,05 जून 2026। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के बाद अब राज्य सरकार स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 108 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को चिन्हांकित कर लिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने जेडी और डीईओ को पत्र लिखकर चिन्हांकित स्कूलों का पूरा सेटअप और शिक्षकों की संख्या की जानकारी मांगी है। स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की अपडेट जानकारी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय भेजनी होगी। इसी आधार पर उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों और स्टाफ की पदस्थापना होगी।

बिलासपुर संभाग से सबसे ज्यादा 32 स्कूल

108 सरकारी स्कूलों में बिलासपुर संभाग से सबसे ज्यादा 32 स्कूल शामिल हैं। दुर्ग संभाग के 26, रायपुर के 25 स्कूलों को योजना में लिया गया है। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा संभाग के स्कूल भी शामिल किए गए हैं।

प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं मिलेंगी

इन 108 स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अपग्रेड कर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सेटअप बदलने के साथ शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। सेजेस के बाद सरकार का यह शिक्षा में दूसरा बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में अब महज 24 घंटे में मिलेगा श्रम पहचान पंजीयन प्रमाणपत्र

रायपुर,05 जून 2026। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है, जो 3 जून 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है। संशोधित नियमों के तहत अब किसी भी दुकान या स्थापना के लिए श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के मात्र 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए नियोक्ताओं को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करना होगा। यह पूरी व्यवस्था स्व-घोषणा पर आधारित और सिस्टम-जनरेटेड होगी, जिसमें किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत जारी सभी श्रम पहचान संख्या प्रमाणपत्र अधिनियम के अंतर्गत पूर्णतः वैध माने जाएंगे। इसके साथ ही, श्रम विभाग के पोर्टल पर दुकानों और प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिससे अभिलेखों का डिजिटलीकरण और उनकी निगरानी बेहद आसान हो जाएगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि आवेदन में कोई भी जानकारी, तथ्य या दस्तावेज गलत अथवा भ्रामक पाए जाते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता की होगी। इसके अलावा, सभी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान परिसर में नाम-पट्ट के साथ इस पंजीयन प्रमाणपत्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

धान घोटाला मामला : हाईकोर्ट में समिति प्रबंधन ने कहा...चूहों ने खाया 690.70 क्विंटल धान...

कोर्ट ने खारिज की एफआईआर रद्द करने की याचिका

बिलासपुर,05 जून 2026। सोसायटी में रखे गए 690.70 क्विंटल धान के चूहों, कीडों एवं सूखेपन से गायब होने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने सोसायटी प्रबंधक द्वारा पेश याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें, कि सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड दुर्ग के शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने सोसायटी के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी में हुई। याचिकाकर्ता अतुल वर्मा सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हली, तहसील पाटन, जिला दुर्ग में सोसायटी मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है। सोसायटी और अधिकारियों के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक खरीदे गए धान को मार्केटिंग फेडरेशन को 31 मार्च, 2026 को या उससे पहले उठाना था। लेकिन बार-बार कहने के बावजूद, धान तय समय में नहीं उठाया गया और लंबे समय तक खरीद सेंटर पर रखा रहा। सोसायटी में 690.70 क्विंटल धान की कमी पाई गई। कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, दुर्ग के जामगांव ब्रांच की शिकायत में कहा गया है, कि खरीफ मार्केटिंग साल 2025-26 के दौरान सेवा सहकारी समिति मर्यादित,कुम्हली में कुल 53,956.40 क्विंटल धान खरीदा गया था, और पूरा स्टॉक 1.4.2026 तक ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था।

इसके बाद 23.04.2026 को, फूड डिपार्टमेंट और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खरीद सेंटर का फिजिकल वेरिफिकेशन किया और कथित तौर पर 21,41,170/- रुपये कीमत के 690.70 क्विंटल धान और 2,13,645/- रुपये कीमत के 3,057 बोरों की कमी पाई गई। निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों की तरफ से जारी किए गए कम्युनिकेशन के आधार पर, यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता, जो सोसाइटी मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, उसने 23,54,815/- की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया। मामले की जांच कराई गई। जांच में इस कमी के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया। जिसे लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

दर्ज एफआईआर को रद्द करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा उक्त धान मौसम, सूखत, चुहों, कीडों के हमला एवं बोरी खराब होने के कारण हुआ है। इसे रोक पाना संभव नहीं है। इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता एवं शासन के पक्ष को सुनने के बाद याचिकाकर्ता की एफआई आर रद्द करने की याचिका को खारिज किया है।

यूनिफार्म नीति में बदलाव,अब छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 2-2 सेट में होंगे बच्चों के ड्रेस

रायपुर,05 जून 2026। छत्तीसगढ़ में वर्षों पुरानी व्यवस्था को बदल दिया गया है। साय सरकार ने इस बार 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक साथ स्कूल यूनिफॉर्म के 2-2 सेट देने का फैसला किया है। अब तक स्कूल शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा मिशन से बताया गया है कि 10 जून तक प्रदेश के सभी जिलों में दोनों सेट यूनिफार्म पहुंचा दिए जाएंगे। शिक्षा सचिव आईएएस डॉ कमलप्रीत सिंह ने इसकी पुष्टि की है। अफसरों के मुताबिक 16 जून को शाला प्रवेश उत्सव के दिन ही बच्चों को सीधे तैयार यूनिफॉर्म के दोनों सेट मिल सकें। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने नया ड्रेस कोड भी लागू किया है, जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चों को नए सत्र के पहले ही दिन से एक नया और एक समान लुक देखने को मिलेगा। राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म तैयार करने का जिम्मा प्रदेश के 2,001 महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा है। इससे ग्रामीण और स्थानीय महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है। अधिकृत सूत्रों के अनुसार बस्तर संभाग में 8 लाख 16 हजार 692 यूनिफॉर्म की मांग थी, जहां अब तक शत-प्रतिशत (100%) सप्लाई पूरी हो चुकी है। सरगुजा संभाग में 8 लाख 4 हजार 130 यूनिफॉर्म की शत-प्रतिशत आपूर्ति कर दी गई है। बिलासपुर संभाग में 6 लाख 52 हजार 876 यूनिफॉर्म की मांग के अनुसार पूरी सप्लाई हो चुकी है। दुर्ग संभाग में कुल 10 लाख 17 हजार 697 गणवेश की मांग है, जिसमें से तेजी से तैयार कर खेप भेजी जा रही है।

श्रम विभाग की सेवाओं के लिए तय हुई समय-सीमा,लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी...

रायपुर,05 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता और मजदूरों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के श्रम विभाग ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अपनी सभी प्रमुख सेवाओं को अधिसूचित कर दिया है। अब विभाग की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे,क्योंकि हर काम के लिए अब दिन तय कर दिए गए हैं। दरअसल,छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धाराओं का प्रयोग करते हुए श्रम विभाग ने मंत्रालय (महानदी भवन,नवा रायपुर) से यह कड़क आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि अब तक विभाग की कई सेवाओं के लिए लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था। मैदानी सूत्रों ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत न सिर्फ काम पूरा करने की समय-सीमा (कार्य दिवस) तय की गई है, बल्कि जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है।

इन तीन स्तरों पर तय हुई जिम्मेदारी

प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए विभाग ने तीन प्रमुख पदों को साफ तौर पर नियुक्त किया है:

पदाभिहित अधिकारी

यह वह अधिकारी होगा जिसके पास आप अपना आवेदन जमा करेंगे और जो तय समय के भीतर आपका काम पूरा करने के लिए सीधे जिम्मेदार होगा।

सक्षम अधिकारी

अगर तय समय में आपका काम नहीं होता है, तो आप इस अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

अपीलीय प्राधिकारी

सबसे बड़ा फैसला लेने का अधिकार इनके पास होगा। अगर निचले स्तर पर सुनवाई नहीं होती, तो अपीलीय प्राधिकारी दोषी अधिकारी पर सीधे कार्रवाई या जुर्माना तय कर सकते हैं।

बिलासपुर में डूबने से दो भाइयों की मौत : तालाब में नहाते समय गहराई में डूब गए दोनों,पुलिस ने लोगों की मदद से बाहर निकाला

बिलासपुर,05 जून 2026। बिलासपुर में शुक्रवार को तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों तालाब में नहाते समय गहराई में समां गए। इस हादसे के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शव को बाहर निकाला। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दो भाइयों की मौत से परिवार में मातम छा गया। घटना सीपत थाना क्षेत्र की है। ग्राम नरगोड़ा के लुदियापारा निवासी किशोर कुमार खरे दिल्ली में रहते हैं। उनके पिता के निधन के बाद वे अपने परिवार के साथ गांव आए हुए थे। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे उनके बेटे ऋषभ कुमार खरे (11 वर्ष) और रितेश कुमार खरे (13 वर्ष) अपने दोस्त निहाल के साथ गांव के नए तालाब में नहाने गए थे। नहाने के दौरान दोनों भाई अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।

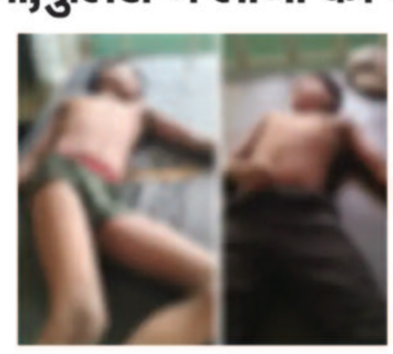

दोस्त ने परिवार वालों को दी जानकारी : इस दौरान दोनों बच्चों को पानी में डूबते देख निहाल डर गया। वह तुरंत बस्ती तरफ गया और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। बच्चों के डूबने की जानकारी मिलते ही परिवार के सदस्य और ग्रामीण तालाब की ओर दौड़े।

घंटों मशक्कत के बाद निकाला शव : इस दौरान गांव के जोगीराम सूर्यवंशी समेत अन्य लोग तालाब में कूदकर दोनों बच्चों की तलाश शुरू की। इस बीच घटना की सूचना सीपत पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घंटों मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को पानी से बाहर निकाला गया। दोनों मासूमों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद दोनों शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

मां का रो-रोकर बुरा हाल : इस हादसे के बाद परिवार का माहौल पूरी तरह मातम में बदल गया है। कुछ घंटे पहले तक जिन बच्चों की किलकारियों से घर गूंज रही थी, उनके हमेशा के लिए चले जाने का सदमा परिजन सहन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक स्थिति बच्चों की मां की है, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। गांव की महिलाएं और रिश्तेदार उन्हें संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बेटे खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

टीचर ने वकील बतौर रखा अपना पक्ष,हाईकोर्ट से मिली राहत

बिलासपुर,05 जून 2026। बच्चों की पढ़ाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए एक व्याख्याता ने न सिर्फ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बल्कि अपने मामले की पैरवी भी खुद की। हाईकोर्ट ने शिक्षक की परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को उनके स्थानांतरण आवेदन पर 45 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के हाई स्कूल मरकेली में

पदस्थ व्याख्याता गया राम दुबे ने किसी अधिवक्ता की सहायता लेने के बजाय स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ को बताया कि उनके बच्चे भिलाई में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और परिवार में उनकी देखरेख करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है। वर्तमान पदस्थापना स्थल और भिलाई के बीच लगभग 150 किलोमीटर की दूरी होने से उन्हें लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जून 2025 में उनका तबादला बालोद जिले के कुमुदकट्टा से मरकेली किया गया था। करीब एक वर्ष तक सेवा देने के बाद उन्होंने एक अप्रैल 2026 को दुर्ग संभाग के संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा के समक्ष बालोद या दुर्ग जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया, लेकिन विभाग ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने भी आवेदन पर निर्णय लेने के अनुरोध का विरोध नहीं किया। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन विभाग के समक्ष लंबित है।

शराब-डीएमएफ घोटालों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा...ढेबर-टुटेजा नेटवर्क की 1400 करोड़ से ज्यादा संपत्ति कुर्क

रायपुर,05 जून 2026। छत्तीसगढ़ में शराब, डीएमएफ, नकली होलोग्राम और प्लेसमेंट घोटालों की जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क से जुड़ी 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन मामलों में करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के प्रमाण सामने आए हैं। जांच के केंद्र में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और कारोबारी

अनवर ढेबर हैं,जिन्हें एजेंसियां इन कथित घोटालों का प्रमुख संचालक मान रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न योजनाओं और सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ अर्जित किया गया, जिसकी जांच अब अंतिम चरणों में पहुंच रही है।

शराब घोटाले में सबसे बड़ी कार्रवाई

ईडी की जांच के अनुसार शराब कारोबार से जुड़े मामले में अब तक 85 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी दुकानों के माध्यम से अवैध शराब बिक्री का समानांतर तंत्र संचालित किया गया,जिससे हजारों करोड़ रुपये का अवैध मुनाफा कमाया गया। जांच में यह भी दावा किया गया है कि शराब की प्रत्येक पेटी पर अवैध वसूली की व्यवस्था बनाई गई थी।

डीएमएफ और अन्य मामलों की भी जांच तेज

जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) फंड के उपयोग में कथित अनियमितताओं को लेकर भी जांच जारी है। आरोप है कि ठेका प्रक्रियाओं में प्रभाव का इस्तेमाल कर पसंदीदा कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और कमीशनखोरी का नेटवर्क विकसित किया गया। इसके अलावा नकली होलोग्राम और प्लेसमेंट से जुड़े मामलों में भी करोड़ों रुपये की गड़बड़ी की आशंका जताई गई है।

संपतियों पर एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई...

जांच के दौरान विभिन्न शहरों में स्थित व्यावसायिक परिसरों,जमीनों,होटलों,कंपनियों के बैंक खातों,निवेश योजनाओं और अन्य संपत्तियों को जब्त या कुर्क किया गया है। एजेंसियों का दावा है कि इनमें से कई संपत्तियां कथित तौर पर अवैध कमाई से अर्जित की गई थीं। कुर्क संपत्तियों में रायपुर और अन्य स्थानों की अचल संपत्तियां,होटल, शेल कंपनियों से जुड़े निवेश,बैंक खाते,म्यूचुअल फंड,आभूषण और नकदी शामिल हैं। जांच एजेंसियां इन परिसंपत्तियों के वित्तीय स्रोतों की भी पड़ताल कर रही हैं।

पीएमएलए के तहत आगे बढ़ेगी कार्रवाई...

ईडी ने मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप पत्र दायर कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि सभी मामलों में जुटाए गए दस्तावेजी और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी विभिन्न अदालतों में खारिज हो चुकी हैं।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)